सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 240 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 13 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

वायुसेना का एएन-32 मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त

गुवाहाटी। असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का एक AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के तुरंत बाद आग की चपेट में आ गया। इस घटना के बाद एयरबेस पर अफ़रा-तफ़री मच गई और तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, उसमें अचानक आग लग गई और उससे घना धुआं उठने लगा। यह नजारा काफी भयावह था, जिसे देखते ही एयरपोर्ट और वायुसेना की फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया, ताकि आग फैलने से रोका जा सके।

छत्तीसगढ़ में मछलियां पकड़ने पर लगा बैन

रायपुर। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है और उनके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।

रायपुर की पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में लगी आग

रायपुर। राजधानी रायपुर के पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना उरला थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में सैंपल लेने के दौरान वाल्व बंद नहीं होने से गर्म पदार्थ बाहर बह गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सेल्फ इग्नीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे आग भड़क उठी। घटना के दौरान सैंपल ले रहे एक कर्मचारी के हाथ में हल्की चोट आई है। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

देश को पहली बार आईएमए से मिलीं नौ महिला सैन्य अफसर, राष्ट्रपति बोलीं- यह बदलती तस्वीर

देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में शनिवार को एक और इतिहास रचा गया। अकादमी की पासिंग आउट परेड (पीओपी) में पहली बार नौ महिला सैन्य अफसर पासआउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनीं। पास आउटपरेड में विशेष रूप से शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पल को देश की बदलती तस्वीर और महिला सशक्ती करण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

इस ऐतिहासिक समारोह में कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सैन्य जीवन की नई शुरुआत की। इनमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल रहे।आईएमए के ऐतिहासिक मैदान में सुबह से ही उत्साह और गौरव का माहौल रहा। परेड की शुरुआत सुबह 6:40 बजे हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैटवुड भवन पहुंचीं और परेड की सलामी ली।

इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कदमताल करते हुए कैडेट्स ने सैन्य अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना का प्रदर्शन किया।

परेड का सबसे खास और ऐतिहासिक क्षण वह रहा, जब पहली बार आईएमए से प्रशिक्षित नौ महिला कैडेट्स सैन्य अफसर के रूप में पासआउट हुईं। इस वर्ष की पासिंग आउट परेड में शामिल 515 कैडेट्स में नौ महिला कैडेट्स सहित कुल 481 भारतीय कैडेट थे। इनके अलावा 16 मित्र देशों के 34 कैडेट्स ने भी प्रशिक्षण पूरा किया और अपने-अपने देशों की सेनाओं का हिस्सा बने। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें नव नियुक्त सैन्य अधिकारियों के कंधों पर रैंक सजाई गई।

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य, शिक्षा विभाग का निर्देश, अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग

नए शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होगी व्यवस्था- सुबह की प्रार्थना से लेकर छुट्टी के समय तक का शेड्यूल तय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति से गहराई से जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रदेश की सभी शालाओं में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के नियमित व अनिवार्य संचालन के कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से जारी इस आदेश के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (ष्ठश्वह्लह्व) को अपने-अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों में अब प्रतिदिन तीन अलग-अलग समय पर निर्धारित क्रम में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रात:कालीन सत्र स्कूल प्रारंभ होने पर सुबह की प्रार्थना सभा में एक तय क्रम के अनुसार ये प्रस्तुतियां अनिवार्य होंगी। विद्यालय प्रारंभ होने पर प्रात:कालीन प्रार्थना सभा में क्रमश: राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीपमंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र तथा महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराया जाएगा। इसी प्रकार मध्यान्ह भोजन के समय विद्यार्थियों द्वारा भोजन मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा। वहीं विद्यालय की छुट्टी के समय संध्या सत्र में राज्यगीत, गायत्री मंत्र एवं शांति मंत्र का सामूहिक वाचन कराया जाएगा।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन स्कूलों का औचक निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं। निर्धारित क्रम में अवहेलना पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन या प्राचार्यों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

बौद्धिक और नैतिक विकास है मुख्य उद्देश्य

स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि इन गतिविधियों के नियमित और प्रभावी संचालन से छात्रों में न केवल राष्ट्रप्रेम और अनुशासन की भावना मजबूत होगी, बल्कि उनके भीतर नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का भी सही विकास होगा। यह पहल विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित कराने में मील का पत्थर साबित होगी।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल प्रवेश उत्सव मनाने आदेश जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद 16 जून के बाद से स्कूल खुलने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। यानी 16 जून से ही स्कूल खुलेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाने के लिए तैयार रहें।

बता दें कि 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। अब अवकाश खत्म होने के बाद प्रदेश के स्कूलों का संचालन 16 जून से नियमित रूप से होगा। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, प्रदेशभर में 16 जून 2026 से शाला प्रवेश उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रवेश उत्सव को एक उत्सव का रूप देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके तहत गांवों और शहरी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। बैनर-पोस्टर और रैलियों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला विकास समितियों और पालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों, परिसरों और कक्षाओं की पूरी साफ-सफाई और आवश्यक मरम्मत कर ली जाए। मरम्मत योग्य भवनों का काम 15 जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया है।

शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक होगा अटेंडेंस ऑनलाइन देनी होगी लीव एप्लीकेशन

■ 16 जून से होगा लागू, लापरवाही पर रुकेगा जून का वेतन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अब ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश आवेदन व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, आगामी 16 जून 2026 से सभी के लिए डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमों की अनदेखी करने पर जून महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।

शासन ने विभाग के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए दो अलग-अलग डिजिटल माध्यम तय किए हैं। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और बाबुओं को आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणालीके जरिए अपनी हाजिरी लगानी होगी।

हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं

16 जून से किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति VSK App या बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज नहीं पाई जाती है, तो उसकी उपस्थिति को शून्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी का जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

ऑफलाइन छुट्टी पर पूर्ण प्रतिबंध

संचालनालय ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग के कर्मियों के अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति के लिए 'HRMIS पोर्टल' की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अब भी ऑफलाइन (कागज पर) आवेदन लिए जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अब ऑफलाइन अवकाश आवेदनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सभी प्रकार की छुट्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली और मंजूर की जा सकेंगी।

अधिकारियों को निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण व संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

भारतीय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट सफल, 5000 किमी से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा

यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश

नईदिल्ली। भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए गए, जिनमें मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम का प्रदर्शन किया गया।

इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) क्लास तक के खतरों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता भी शामिल है। यह स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जून को टेस्टिंग की तस्वीरें एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं।

इसके साथ-साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का भी टेस्ट किया गया। इसे भारत की समुद्री स्ट्राइक और डिफेंस स्किल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत अब उन खास देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनके पास ऑपरेशनल-लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास थी।

प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब एएन-32 विमान जोरहाट हवाई पट्टी पर उतरने का प्रयास कर रहा था। हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच कराई जाएगी और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है। फिलहाल प्रशासन और वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

संपादकीय

निरंकुशता के निशाने

अक्षम्य है भारतीय नाविकों का मारा जाना

खाड़ी में ईरान की नाकेबंदी की कवायद के दौरान अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों का मारा जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको लेकर देश में गम व गुस्सा व्याप्त है। यूं तो कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और क्वॉड जैसे संगठनों में भूमिका निभा रहा है, तो फिर लगातार भारत के हितों पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? भले ही अमेरिका ईरान की तेल निर्यात से होने वाली आय रोकने व युद्ध समाप्त करने हेतु समझौते के लिये दबाव बनाने हेतु ये आक्रामक नीति अपना रहा हो। लेकिन जिन देशों का युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनके नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है हाल ही में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को अमेरिकी सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। इसमें से, ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय चालक दल के तीन सदस्य मारे गये हैं। जिससे भारत व अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वैसे औपचारिक विरोध दर्ज करते हुए भारत ने दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। इसके बावजूद भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक रवैया दर्शाने वाले अमेरिका के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद कि भारत क्वॉड में अमेरिका का साझेदार है। विडंबना यह भी है कि जो सूत्रधार संगठन के जरिये समुद्री आवाजाही को स्वतंत्र बनाने की बात करता है, वही अमेरिका इसमें बाधक बना है। भले ही अमेरिका इन जहाजों के प्रतिबंधित होने की बात कहे, या जहाज भारतीय न हों, लेकिन उनमें चालक दल के सदस्य तो भारतीय थे। इसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से अमेरिका के खुफिया तंत्र को जरूर रही होगी। अमेरिका को सार्वजनिक रूप से भारतीय नाविकों के मारे जाने पर खेद जताना चाहिए। निश्चय ही भारत के निकट के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का निरंकुश व्यवहार निंदनीय है। कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इस मुद्दे को सख्ती से अमेरिका के सामने उठाना चाहिए था।

> “ जिन देशों का युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनके नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है हाल ही में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को अमेरिकी सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। इसमें से, ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय चालक दल के तीन सदस्य मारे गये हैं। जिससे भारत व अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वैसे औपचारिक विरोध दर्ज करते हुए भारत ने दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। इसके बावजूद भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक रवैया दर्शाने वाले अमेरिका के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की मांग की जा रही है।

तमाम भारतीयों को इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया उदार लगती है। सवाल पूछा जा रहा है कि यदि तीन अमेरिकी नागरिक मारे जाते तो क्या अमेरिका चुप बैठता? कहा जा रहा है कि भारत का कड़ा विरोध सामने न आने के कारण होर्मुज स्ट्रेट के पास पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय के मारे जाने की घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चा हुई है। विडंबना है कि अमेरिकी सेना ने एक सप्ताह में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को निशाना बनाया। हालांकि, सोमवार को हुए हवाई हमले के बाद ओमानी अधिकारियों ने 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया था। दरअसल, ट्रंप प्रशासन की निरंकुशता के चलते ही अमेरिका रवैया वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कारोबारी जहाजों को निशाना बनाने का क्या औचित्य है? अमेरिका को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह तटस्थ देशों के नागरिकों को निशाना बनाये? क्यों भारतीय नागरिक अमेरिका व ईरान के बीच जारी संघर्ष की कीमत चुकाएं? इस तरह का शक्ति प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है तथा स्वतंत्र नौवहन के मार्ग में बाधक है। भारतीयों का गुस्सा तब कम हो जाता यदि अमेरिका मरने वाले नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर देता। सही मायने में अमेरिका भारत को अपने कारोबारी हितों के साधन के रूप में तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारतीय आत्मसम्मान व संप्रभुता का मान नहीं रखता। भारत को बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी कूटनीति का निर्धारण करना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि भारत एक उभरता बाजार ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। अब चाहे सामने अमेरिका हो या चीन जैसे कोई अन्य देश। भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कई जहाज भारत के स्वामित्व वाले न हों, लेकिन चालक दलों में शामिल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए।

ऐतिहासिक कार्यकाल, परिवर्तनकारी नेतृत्व

सीपी राधाकृष्णन

भारत ने 10 जून, 2026 को अपने लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज किया। इस रोज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में निर्बाध सेवा के 4,399 दिन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को ही नहीं दिखाती। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के लोगों के अडिग विश्वास और आस्था को भी प्रतिबिंबित करती है। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास के लिए अथक प्रतिबद्धता तथा भारत की अवाम के कल्याण और आकांक्षाओं प्रति अटूट निष्ठा को प्रतिबिंबित करती है।

परिवर्तनकारी नेतृत्वः 4,366 दिन और आगे

नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के प्रधान सेवक के रूप में भारत में सुशासन और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों पर आधारित अभूतपूर्व परिवर्तन के युग की शुरुआत की है। इतिहास अब्राहम लिंकन को मानव दासता का अभिशाप खत्म कर लाखों लोगों की गरिमा बहाल करने में उनके अडिग नेतृत्व के लिए उनका आदर करता है। इसी तरह, आने वाली पीढ़ियां 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पूर्ण निर्धनता से बाहर निकालने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करेंगी। उनकी दृष्टि, अथक प्रयासों और परिवर्तनकारी शासन ने अनगिनत परिवारों को अवसर, गरिमा और उम्मीद देकर सशक्त बनाया है तथा वे आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य के आश्वासन को अपनाने में समर्थ बने हैं। उनका योगदान मानवता की सेवा में एक युगांतरकारी उपलब्धि के रूप में इतिहास में दर्ज रहेगा।

इतना ही नहीं, उनकी परिवर्तनकारी पहलकदमियों ने शिक्षा, आवासन, स्वच्छता, स्वास्थ्यसेवा और खाद्य निश्चितता के माध्यम से करोड़ों लोगों की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक, आयुष्मान भारत योजना के जरिए 44 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यसेवा प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल पहुंचा कर अनगिनत परिवारों को गरिमा प्रदान की और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। निःशुल्क खाद्यान्न के 2020 से जारी प्रावधान से लगभग 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा की रक्षा होने के अलावा यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी कमजोर नागरिक पीछे नहीं छूटने पाए। इसके अतिरिक्त, 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों का सुरक्षित और स्थाई घर का मालिक बनने का सपना पूरा हुआ जिससे उनमें सुरक्षा, गरिमा और भविष्य के लिए उम्मीद की भावना मजबूत हुई है। कुल मिला कर, ये पहलकदमियां एक सहृदय शासन और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के स्थाई प्रतीक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया है चाहे वे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों या वंचित वर्ग के लोग। 3 करोड़ से ज्यादा 'लखपति दीदियों' का सामने आना महिला नेतृत्व में विकास के उनके दृष्टिकोण का एक सशक्त प्रमाण है, जबकि 'नारी शक्ति' के तहत शुरू की गई पहलों ने महिलाओं को देश के निर्माण में और भी अहम भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। नए आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना से भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा तेज़ी से बढ़ा है, जिससे देश के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति देखी है। वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के तेज़ी से विस्तार से लेकर दूर-दराज़ के इलाकों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं तक, उनके नेतृत्व में एक आधुनिक, आपस में जुड़े हुए और महत्वाकांक्षी भारत की नींव रखी है। इन उपलब्धियों ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि देश भर के लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है।

भारत डिजिटल नवाचार, सेमी-कंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वैक्सीन बनाने और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जिससे उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्व में हमारे देश की स्थिति और मजबूत हुई है।

विकास भी, विरासत भीः तमिल विरासत का सम्मान, तमिलनाडु का विकास

समकालीन नेताओं में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो बात सबसे अलग और अनूठी बनाती है, वह है उनका यह दृढ़ विश्वास कि विकास और परंपरा कोई परस्पर विरोधी विचार नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। विकास भी, विरासत भी की अपनी दूरदर्शी सोच के ज़रिए उन्होंने यह दिखाया है कि कोई देश अपनी सभ्यतागत विरासत से जुड़े रहते हुए भी तेज़ी से आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ सकता है।

उनके नेतृत्व में, भारत ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग और समाज कल्याण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास किया है और इसके साथ ही अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषाओं, आध्यात्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक नए गौरव का अनुभव किया है। चाहे पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार हो, सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुत्थान हो, शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना या अमूल्य कलाकृतियों का संरक्षण हो- उनके शासन में आधुनिक आकांक्षाओं और शाश्वत मूल्यों का दुर्लभ समन्वय देखने को मिलता है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नज़रिए ने राष्ट्र-निर्माण की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा है। उन्होंने यह साबित किया है कि असली विकास का पैमाना सिर्फ़ आर्थिक तरक्की नहीं है, बल्कि इसे इस बात से भी मापा जाता है कि एक राष्ट्र अपनी विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने, संजोने और सौंपने में कितना सक्षम है। उनकी विकास भी, विरासत भी की सोच एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते भारत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई है, जो अपने गौरवशाली अतीत से मज़बूती से जुड़े रहते हुए भविष्य की ओर निडरता से कदम बढ़ा रहा है।

इस सोच का सबसे ज्यादा फ़ायदा तमिलनाडु और दुनिया भर में फैले तमिल समुदाय को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को अभूतपूर्व पहचान, सम्मान और समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही परिवर्तनकारी पहलों से तमिलनाडु को बहुत लाभ हुआ है, जिनमें चेन्नई मेट्रो रेल का विस्तार, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और नया पाम्बन रेल पुल शामिल हैं। भारत के पहले वर्टिकल-लिफ्ट सी-ब्रिज, नए पाम्बन रेल पुल का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो रामेश्वरम के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है और भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के निरंतर और दृढ़ प्रयास के कारण, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर भी उभरा है।

पूर्व के किसी भी प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत को उस निरंतरता, प्रमुखता और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जैसा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उन्होंने तमिल सभ्यता को एक नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। भारत और विदेशों में तमिल की प्राचीनता और साहित्यिक समृद्धि का उनके द्वारा लगातार किया गया गौरवगान दुनिया भर के तमिलों के दिलों को गहराई से छू गया है। इस गहरे संदेश को वैश्विक मंच पर लाकर, उन्होंने दुनिया को तमिल संस्कृति में निहित शाश्वत मानवीय मूल्यों और उसकी समृद्ध सभ्यतागत विरासत से परिचित कराया। मानवता को यह एहसास हुआ कि कार्ल मार्क्स से सदियों पहले ही तमिलों ने एक मानवता के नेक विचार को अपनाया था। वसुधैव कुटुंबकम की पहल भी इसी दर्शन पर आधारित है।

'काशी-तमिल संगमम' और 'सौराष्ट्र-तमिल संगमम' जैसी पहलों ने सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत किया है और उन स्थायी सभ्यतागत रिश्तों को उजागर किया है जो हमारे देश को एकजुट करते हैं। हमारे नए संसद भवन में 'सेंगोल' की स्थापना, भारत की लोकतांत्रिक और सभ्यतागत विरासत में तमिलनाडु के योगदान की एक सटीक पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गंगईकोंडा चोलपुरम की यात्रा चोल वंश की विरासत को उजागर करती है। साथ ही, विदेशों से बेशकीमती कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की व्यापक रूप से सराहना की गई है, इनमें हाल ही में अनाईमंगलम से मिली चोल-युगीन तांबे के ताम्रपत्र भी शामिल हैं। मंदिरों, धरोहर स्थलों, शास्त्रीय साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए उनके समर्थन के साथ-साथ, इन प्रयासों ने विश्व में तमिल सभ्यता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और तमिल भाषा व संस्कृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को भी दर्शाया है।

हर दौर में इतिहास ऐसे नेताओं के उदय का गवाह रहा है, जिनकी सोच और काम उनके समय की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। ऐसे लोगों को 'युग पुरुष' के तौर पर याद किया जाता है क्योंकि वे देश की नियति बदलते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अपने परिवर्तनकारी नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनता की अथक सेवा के माध्यम से, वह समकालीन भारत के एक सच्चे 'युग पुरुष' के रूप में उभरे हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कुशल नेतृत्व राष्ट्र को 'विकसित भारत @ 2047' की ओर ले जाएगा।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)

राजनीतिक सोच की गरीबी का त्रास झेलता पंजाब

प्रोफेसर सुखदेव सिंग

राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में राजनीति मुनाफा कमाने का एक ऐसा धंधा बन गया है, जिसमें लोगों के लिए काम करने की जगह व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीतिक दल बदली एक आम प्रक्रिया हो गई है। चुनाव जीतने के लिए किसी राजनीतिक प्रेरणा या पॉलिसी के बजाय पैसे, पावर और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल आम हो गया है। अपने नुमाइंदे चुनते समय, राजनीतिक पार्टियां उसकी राज्य में जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण, बिगड़ती शहरी सेवाओं, हेल्थ और एजुकेशन को सही दिशा देने के लिए लोगों के हित में एक ठोस पॉलिसी बनाने की क्षमता के बजाय चुनाव क्षेत्र में उसके परिवार के कंट्रोल और पैसे खर्च करने की उसकी क्षमता और सहमति को प्राथमिकता दे रही हैं।

आज़ादी के बाद से लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सत्ता की अदला-बदली करते रहे हैं, लेकिन 2022 से पॉलिटिकल पावर का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास है; जबकि भविष्य में भाजपा राज्य की बागडोर संभालने के लिए बेचैन हो रही है। सरकार द्वारा पंजाब को आर्थिक कर्ज़ से आज़ाद करने और लोगों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कोई पक्का प्रोग्राम बनाने के बजाय, राज्य में मुफ़्त आटा, दाल, मुफ़्त बिजली, मुफ़्त बस यात्रा, मुफ़्त तीर्थयात्रा और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मुफ़्त देने वगैरह का लालच देकर थोड़े समय की लोकप्रियता हासिल की जा रही है। टिकाऊ सुधारों के बजाय तुरंत चुनावी फायदे को तरजीह दी जा रही है, लेकिन न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने से बचा जा रहा है। पंजाब के 'दस उंगलियों से काम करने और बांटकर खाने' वाले उसूल को कमज़ोर किया जा रहा है और लोगों को बेकार बनाया जा रहा है।

दूसरी तरफ, भाजपा के नेता 'डबल इंजन सरकार' का नारा लगा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि अगर उन्हें देश के खाते से कुछ पाना है, तो राज्य में उसी पार्टी को चुना जाए, जिसकी केंद्र में सरकार हो। यानी भाजपा केंद्र से आर्थिक सहायता का लालच देकर पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में है। भाजपा वादा कर रही है कि अगर वह चुनाव जीतती है, तो राज्य में धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून बनाएगी। कुछ समय पहले भाजपा ने राज्य में कांग्रेस के फ्रंटलाइन नेताओं का पार्टी परिवर्तन कर के अपनी पार्टी में शामिल किया था, वहीं हाल ही में उसने आप के 6 राज्यसभा सदस्यों को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा लिया।

गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यों के पार्टी परिवर्तन से कुछ दिन पहले ही उनमें से एक सदस्य के घर पर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने छापा मारा था और अगले ही दिन उन की पार्टी परिवर्तन की घटना हो गई। दूसरी तरफ आप में पंजाब के 6 में से 2 पार्टी परिवर्तन वाले सदस्य गैर पंजाबी हैं। राजनीति में अनजान और कच्ची समझ रखने वाले, लेकिन उस समय आप ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक को हीरो की तरह पेश करके, उन्हें पंजाब में बिना किसी संवैधानिक दायित्व के बहुत ज़्यादा पावर, राज्य के खर्च पर सिक्योरिटी देकर, और फिर उन्हें पंजाब से राज्यसभा मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट करके अपनी पॉलिटिकल नादानी दिखाई है। अगर हम पंजाब के बारे केंद्र सरकार की पॉलिसी देखें, तो हमें वहां भी राजनीतिक गुरबत ही दिखाई देती है। भाजपा की केंद्र सरकार, लोगों की भलाई से ज़्यादा कॉर्पोरेट के फायदे के लिए, पंजाब में खेती को इंडस्ट्रिलाइज़ेशन करने और इसमें लगी 35-40 फीसदी आबादी के एक बड़े हिस्से को खेती के पेशे से हटाने का इरादा रखती है, लेकिन इस आबादी के लिए एक विकल्प के तौर पर एक ठोस और सम्मानजनक काम के लिए कोई भरोसेमंद पॉलिसी लाने में कोई सीरियस नहीं दिखती। राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं द्वारा 'डबल इंजन सरकार' और 'धर्मांतरण विरोधी कानून' की पेशकश भी राज्य में राजनीतिक नासमझी को दर्शाती है। आप के राज्यसभा मेंबरों ने अपने दलबदल को यह कहकर सही ठहराया है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था। लेकिन सच तो यह है कि उनके पास न तो कोई लोगों का एजेंडा था, न सोच और न ही पक्का यकीन और न ही लोगों के हित में कुछ कहने का दम; अगर कुछ था, तो वह था पद और पावर की भूख।

अंत्योदय के कदमः सभी के लिए सम्मान, अवसर और विकास सुनिश्चित करना

पीढ़ियों से, भारत के सबसे वंचित समुदाय हाशिये पर रहे हैं, उन्हें लंबे समय तक कोई सुविधा नहीं मिली। पिछले 12 सालों में यह बदल गया है, जब सरकार ने अंत्योदय को अपना मंत्र बनाया। सबको साथ लेकर चलने वाली और अच्छी शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, रोज़ी-रोटी में मदद, अवसंरचना और सांस्कृतिक पहचान इन समुदायों तक बड़े पैमाने पर पहुंची है। मकसद साफ़ है: यह सुनिश्चित करना कि जो लोग पिछड़ गए थे, उन्हें अवसर और प्रगति में सबसे आगे रखा जाए।

महात्मा गांधी ने एक बार सलाह दी थी, सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने के बारे में सोच रहे हो, क्या वह उसके किसी काम का होगा। दशकों तक, यह शक्तिशाली विचार ज़्यादातर किताबों में ही मिलता था, जबकि लाखों भारतीय, देश की प्रगति से बाहर छूटे रह गए।

हालांकि, पिछले बारह सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत इस आदर्श के बारे में सिर्फ़ बातें करने से आगे बढ़कर इसे अमल में लाने लगा है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जो लोग अंतिम छोर पर थे, उन्हें अवसर, सम्मान और विकास में सबसे पहले जगह मिली है। ध्यान बिखरी हुई डिलीवरी से हटकर अधिकतम लोगों तक सेवाओं को शामिल करने पर आ गया है।

आदिवासी बस्तियों में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। पिछड़े समुदायों के छात्रों को पढ़ाई-लिखाई तक ज़्यादा पहुँच मिली है। सफ़ाई कर्मचारियों को मज़बूत संस्थागत पहचान और सुरक्षा सहयोग मिला है। पिछड़े और खानाबदोश समुदाय लक्षित कल्याण योजना के फोकस में आ गए हैं।

यह बदलाव भौगोलिक भी दिख रहा है। आदिवासी इलाके, आकांक्षी ज़िले और दूर-दराज की बस्तियाँ विकास योजना और निगरानी के केंद्र बन गए हैं। अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल से उन इलाकों में अंतिम छोर तक डिलीवरी मज़बूत हुई, जहाँ कभी पहुँचना मुश्किल माना जाता था।

विकास के केंद्र में आदिवासी समुदाय

भारत के आदिवासी समुदाय हमेशा से संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और मज़बूती से समृद्ध रहे हैं। उनके पास परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पानी, बिजली और रोज़गार के मौकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं तक बराबर पहुँच की कमी थी। पिछले 12 साल इस दूरी को कम करने के लिए रहे हैं- जानबूझकर, पर्याप्त मात्रा में और बड़े पैमाने पर।

यह बदलाव खास तौर पर दूर-दराज की बस्तियों में दिखाई दिया है, जिसमें खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों के रहने वाले इलाके भी शामिल हैं। जिन इलाकों तक पहुँचना कभी मुश्किल माना जाता था, वे अब विकास की योजना और लास्ट-माइल डिलीवरी के केंद्र बन गए हैं।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान एक कार्यक्रम है जो खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों के लिए है। वे भारत के सबसे अलग-थलग समुदायों में से हैं। कई लोग बिना पक्के घर, साफ़ पानी, बिजली या सड़क के रहते थे। सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों के मिलकर किए गए प्रयासों से इन कमियों को पूरा करने के लिए नवंबर 2023 में PM जनमन शुरू किया। यह कार्यक्रम 18 राज्यों और 1 केंशाप्र में 75

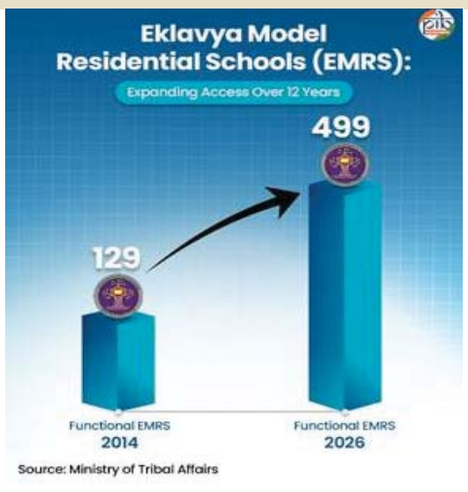

PVTG समुदायों को लक्षित करता है, जो 9 मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 11 इंटरवेंशन के ज़रिए काम करते हैं। कुल बजटीय खर्च 24,104 करोड़ रुपये है।

झारखंड के गरियाबंद ज़िले में, कमार PVTG समुदाय की महिलाएं अपने बड़ों को जंगल की जड़ी-बूटियों से इलाज करते हुए देखकर बड़ी हुईं। यह ज्ञान मांओं से बेटियों को चुपचाप मिलता था। सालों तक, उन्होंने उन जड़ी-बूटियों को कच्चा ही बाज़ार में जो भी दाम मिलता, बेचा। ज्ञान उनका था। लेकिन, कमाई बहुत कम होती थी।

PM जनमन ने इसे बदल दिया। अपने वन धन विकास केंद्र पहल के तहत, इनमें से 87 महिलाएं कुछ अलग बनाने के लिए एक साथ आईं। उन्होंने छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत आयुर्वेदिक तेल, पाउडर और दवाइयाँ बनाने के लिए लाइसेंस लेकर एक यूनिट शुरू की, जिसके पास आयुष सर्टिफिकेशन था। एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के ज़रिए कौशल को बेहतर बनाया गया। शुरुआत से अब तक बिक्री 159.59 लाख रुपयों तक पहुँच गई है। महिलाएं अब अपने गाँव से बाहर जाए बिना उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम संभालती हैं। जो कभी शांत, विरासत में मिला ज्ञान था, वह अब एक अच्छा बिज़नेस बन गया है।

11 इंटरवेंशन में घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से पानी की सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्टल, बिजली, मोबाइल टावर, मल्टीपर्पस सेंटर, वन धन विकास केंद्र और व्यावसायिक कौशल शामिल हैं।

PM जनमन का एक खास हिस्सा वन धन विकास केंद्र बनाना है, जो समुदायों को जंगल से मिलने वाले उत्पाद इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और बेचने में मदद करते हैं। इससे स्थानीय रोज़गार और आय कमाने के मौके बनते हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिज़नेस डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की मदद से 15 राज्यों में स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण दे रहे हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA), जिसे अब PM-JUG के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। यह 17 मंत्रालयों के प्रयासों को जोड़ता है और आदिवासी-बहुसंख्यक गांवों और निजी-जनजाति बस्तियों में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।

(प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान) के तहत, अब सरकार अलग-अलग योजनाओं को अकेले-अकेले लागू करने के बजाय, कई मंत्रालयों और विभागों को मिलाकर एक साथ, एक बड़े मिशन के रूप में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अनुसूचित जनजाति के छात्र के बीच पढ़ाई के मौके बढ़ाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर उभरे हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में बने ये रेजिडेंशियल स्कूल क्लास VI से XII तक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे विकास में मदद देते हैं।

पिछले 12 सालों में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बढ़ने से दूर-दराज के जिलों में आदिवासी पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है। 2018 के बाद यह नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा, जिससे मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूलिंग और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई उन अनुसूचित जनजाति समुदायों के करीब आई जो पीढ़ियों से सुविधाओं से वंचित रहे।

2026 तक, 499 स्कूलों में 1.56 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 323 और स्कूल बन रहे हैं।

EMRS में पढ़े कई छात्र स्ट्रक्चर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षा पाने वाले बन गए।

नए कैंपस में ऐसी सुविधाएं शुरू की गईं जो पहले कई दूर-दराज के इलाकों में नहीं थीं, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षण सुविधाएं और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल शामिल हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

मनरेगा से दुर्ग जिले की 300 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ

दुर्ग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से जिले के 66 हजार 663 से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 3923 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनसे एक ओर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हो रही है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन तथा ग्रामीण अधोसंरचना विकास को भी नई दिशा मिल रही है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे के निर्देशन में जिले में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। साथ ही आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी मिट्टी मूलक निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में जॉब कार्डधारी श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर दुर्ग में विशेष विधिक शिविर आयोजित

दुर्ग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दो काउंसलर विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ प्रदान की। शिविर के दौरान बच्चों को बाल श्रम की परिभाषा, उसके विभिन्न स्वरूपों तथा बाल श्रम उन्मूलन के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य को प्रभावित करता है। वक्ताओं ने बच्चों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, किशोर न्याय से संबंधित प्रावधानों तथा बाल संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न भारतीय कानूनों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों को शासकीय पुनर्वास योजनाओं, शिक्षा के अधिकार तथा बाल संरक्षण तंत्र के बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देकर उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उत्साहपूर्वक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका काउंसलरों द्वारा सरल एवं सहज भाषा में उत्तर देकर समाधान किया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में दुर्ग, भिलाई एवं धमधा क्षेत्र के पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

भिलाई के तीन ट्रैकर ने सफलतापूर्वक पूरा किया एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण ट्रेकों में से एक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को भिलाई एवं दुर्ग के तीन ट्रैकर्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया। यह साहसिक यात्रा 15 मई को भिलाई, छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर 1 जून को भिलाई वापसी के साथ पूरी हुई। कुल 18 दिनों की इस यात्रा में प्रतिभागियों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, अत्यधिक ऊँचाई और प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया।

इस ट्रैकिंग में खुर्सीपार, भिलाई निवासी कोटेश्वर राव रेलवे चरोदा में पदस्थ हैं और हुडको निवासी श्रीमती मिनिराज ने भाग लिया। दोनों ही यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफइंडिया (वाईएचएआई) के लाइफटाइम सदस्य हैं और वाईएचएआई के अनेक राष्ट्रीय एवं स्थानीय ट्रैक में सहभागिता कर चुके हैं। इनके साथ पदमनाभपुर, दुर्ग निवासी श्रीमती निधि जैन भी शामिल थीं, जो काठमांडू से इस अभियान में जुड़ीं। यह संपूर्ण ट्रेक टैप लाइफ एडवेंचर एंड हाई फाइव कंपनी के माध्यम से संपन्न हुआ।

एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक की शुरुआत नेपाल के लुकला से होती है, जहाँ पहुँचने के लिए काठमांडू से हवाई यात्रा करनी पड़ती है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया के सबसे छोटे रनवे और चुनौतीपूर्ण लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। लुकला से ट्रेक प्रारंभ कर पहले दिन दल ने फाकिडंग में रात्रि विश्राम किया।

दूसरे दिन ट्रेकर्स नामचे बाजार पहुँचे, जो इस मार्ग का सबसे बड़ा नगर है। विशेष बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है और केवल पैदल ट्रेकिंग द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। अधिक ऊँचाई के कारण शरीर को वातावरण के अनुरूप ढालने हेतु यहाँ एक अतिरिक्त दिन एक्लाइमेटाइजेशन के लिए रुकना पड़ा। इसी दौरान पहली बार विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट के दर्शन हुए।

इसके बाद दल देबोचे पहुँचा। मार्ग में विश्व प्रसिद्ध टेंग बेचे मॉनेस्ट्री के दर्शन का अवसर मिला। यह वही ऐतिहासिक बौद्ध मठ है जहाँ प्रथम बार एवरेस्ट फतह करने से पूर्व महान पर्वतारोही तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी भी आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। यह मठ अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।

देबोचे से आगे बढ़ते हुए दल डिंग बेचे पहुँचा, जहाँ ऊँचाई और अत्यधिक ठंड के कारण शरीर के बेहतर अनुकूलन के लिए एक अतिरिक्त दिन रुकना आवश्यक होता है। इसके पश्चात ट्रेकर्स लोबुचे के लिए रवाना हुए। इस क्षेत्र में पहुँचते-पहुँचते घने जंगल समाप्त हो जाते हैं और केवल छोटी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कोहरे के बीच ट्रेकिंग का अनुभव अत्यंत रोमांचक रहा।

लिंबाचे में रात्रि विश्राम के बाद दल गोरख शेप पहुँचा। यहाँ आवश्यक सामान लेकर दोपहर भोजन के बाद सभी लंबे समय से प्रतीक्षित लक्ष्य एवरेस्ट बेस कैंप की ओर बढ़े। लगभग तीन घंटे की कठिन पदयात्रा के बाद दल सफलतापूर्वक एवरेस्ट बेस कैंप पहुँच गया।

बेस कैंप पहुँचने की खुशी शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। सभी ट्रेकर्स ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी तथा भारतीय तिरंगे के साथ तस्वीर लेकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। यह वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए पर्वतारोहण अभियानों की शुरुआत होती है। लंबे समय से संजोया गया सपना यहाँ साकार हुआ।

हालाँकि मौसम खराब होने के संकेत मिलते ही दल वापस गोरख शेप लौट आया। लौटने के बाद सभी ने ऊँचाई पर होने वाली समस्याओं का प्रभाव महसूस किया। तेज सिरदर्द और अस्वस्थता के कारण उस रात कोई भी भोजन नहीं कर पाया तथा पूरी रात कठिन परिस्थितियों में बितानी पड़ी। अगली सुबह दल फेरिचे के लिए रवाना हुआ। मार्ग में पुन: लोबुचे और थूकला से होकर गुजरा। नदी किनारे बने सुंदर मार्ग से होते हुए शाम तक सभी फेरिचे पहुँचे।

वापसी यात्रा के अगले दिन दल पुन: नामचे बाजार के लिए रवाना हुआ। मार्ग में देबोचे, टेंगबोचे और फूंकी तांगा से गुजरते हुए सभी ने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। वापसी के दौरान वर्षा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन शाम तक सभी सुरक्षित रूप से नामचे बाजार पहुँच गए और वहीं रात्रि विश्राम किया।

विश्व रक्तदाता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में दो दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। विश्व रक्तदाता दिवस-2026 के अवसर पर 12 जून 2026 को सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र (जेएलएनएच एंड आरसी) के ब्लड सेंटर द्वारा मानवता की एक बूंद - रक्तदान, जीवनदान थीम के साथ दो दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान के प्रथम दिवस अस्पताल कर्मियों एवं स्वैच्छिक रक्तदाताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता से 29 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।रक्तदान अभियान का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने किया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. उदय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने मानव रक्त समूहों की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक डॉ. कार्ल लैंडस्टाइनर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं को जीवन रक्षक योगदान के लिए ट्रॉफी एवं पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

रक्तदान के क्षेत्र में निरंतर सहयोग प्रदान करने वाली विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने इन संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने तथा रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष (पैथोलॉजी) डॉ. मनीषा कांगो, ब्लड सेंटर प्रभारी डॉ. निली एस. कुजूर, वरिष्ठ सलाहकार (पैथोलॉजी) डॉ. प्रिया साहू, सलाहकार (ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज) डॉ. दीपक कुमार दासमहापात्र तथा सलाहकार (पैथोलॉजी) डॉ. प्रतीक शिवप्पा सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में ब्लड सेंटर की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उप प्रबंधक राजीव शर्मा, सहायक प्रबंधक सुश्री रीता भटनागर तथा स्टाफ नर्स सुश्री शैल कुमारी सिंह सहित टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सक्रिय योगदान दिया।

रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग, रक्त संग्रहण एवं प्रसंस्करण से संबंधित तकनीकी कार्यों का संचालन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट शाजी, सुधीर कुमार पाण्डेय एवं अजय कुमार आर्य तथा जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट संदीप कुमार पाण्डेय, मीनाक्षी चरण, कुलदीपक तिवारी एवं जितेन्द्र कुमार द्वारा दक्षतापूर्वक किया गया।

मौर्य को मिला राष्ट्रीय ग्रेट अशोका अवार्ड

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। इस्पात नगरी भिलाई के वरिष्ठ साहित्यकार एनएल मौर्य ''प्रीतम'' को जबलपुर में आयोजित एक सामाजिक सम्मेलन में राष्ट्रीय ग्रेट अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित कला वीथिका सभा हॉल, जबलपुर में यह समारोह हुआ। अशोक प्रबुद्ध समृद्ध भारत मिशन फउंडेशन भारत एवं अखिल भारतीय कुशवाहा समण खत्तीय क्षत्रिय शाक्य मौर्य काछी पाटीदार माली सैनी संयुक्त महासंघ भारत के संयुक्त तत्वावधान में देश भर के सामाजिक बंधु जुटे।

आयोजन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डायरेक्टर डॉ. देवा बोधी अशोक (डॉ. दिनेश पटेल) ने किया। कार्यक्रम में प्रथम ग्रेट अशोका अवार्ड के माध्यम से शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य, संगठन एवं जन जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। साथ ही समाज प्रवर्तन 254 दिवसीय मध्यप्रदेश बाइक यात्रा प्रदर्शनी तथा प्राचीन मौर्य-बौद्ध मठ गोपालपुर लामेटाघाट, जबलपुर की विशेष प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. देवा बोधी अशोक (दिनेश पटेल) ने घोषणा की कि अशोक प्रबुद्ध समृद्ध भारत मिशन का संदेश मध्य प्रदेश की प्रत्येक तहसील, गांव एवं जिले तक पहुंचाने के लिए आगामी 18 माह तक व्यापक जन जागरण एवं कार्य यात्रा अभियान चलाएगा। आयोजन को प्रदेश अध्यक्ष चंद्र मोहन सिंह कुशवाहा (इंदौर), अंतरराष्ट्रीय संरक्षक डॉ. वीर बहादुर महतो (नेपाल), मुख्य अतिथि शिवपूजन कृषिवाहा और विशिष्ट अतिथि तपेंद्र शाक्य (पूर्व आईएएस, लखनऊ) ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे सम्राट अशोक अकादमी के प्रदेश महासचिव एवं साहित्यकार एनएल मौर्य ''प्रीतम'' ने मानव कल्याण, सामाजिक जागरूकता एवं वैचारिक आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने पर बल दिया।

75 लाख रुपये से अधिक के नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के पटरीपार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महापौर अलका बाघमार ने लोककर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 एवं 44 में 75 लाख रुपये से अधिक की लागत से होने वाले नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से जल निकासी और आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने विकास कार्यों

की स्वीकृति एवं भूमिपूजन पर महापौर एवं निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भूमिपूजन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास वार्ड में हिरामन साहू के घर से रानू के घर तक तथा पवन के घर से परऊ यादव के घर के पास तक लगभग 19 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 सिकोला भाठा की विभिन्न गलियों में 18 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य होगा। वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती में मानिकपुरी के घर तक तथा निर्मला के घर से प्रकाश के घर तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य लगभग 18 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। वहीं वार्ड क्रमांक 16 सिकोला बस्ती कर्मचारी नगर में साहू भवन से मुख्य नाला तक 20 लाख रुपये की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य संपादित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर होगी, बारिश के दौरान जल निकासी बेहतर होगी तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, नाली और पुलिया निर्माण के कार्य लगातार स्वीकृत किए जा रहे हैं। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव और आवागमन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा पटरीपार क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का स्तर और बेहतर होगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में पार्षद ललिता ठाकुर, युवराज कुंजाम, खिलावन मटियारा, रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष मनमोहन सिंह, सहायक अभियंता संजय ठाकुर,उप अभियंता सिद्धार्थ साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने विकास कार्यों के लिए नगर निगम एवं महापौर का आभार व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने की अपेक्षा जताई।

सीसीपीएल 2026 : आयुष की हैट्रिक से रायपुर पस्त, रायगढ़ फाइनल में, बिलासपुर से होगा मुकाबला

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सीसीपीएल 2026) अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रतियोगिता के दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। दोनों मैच लो स्कोरिंग रहे। पहले मैच में बिलासपुर ने बस्तर को हराया वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रायपुर को रायगढ़ के हाथों हार मिली। रायगढ़ के गेंदबाज आयुष ने हैट्रिक लेकर रायपुर के बल्लेबाजों को पस्त कर दिया। अब रविवार 14 जून को बिलासपुर व रायगढ़ के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

शुक्रवार 12 जून को पहला सेमी फायनल मैच बस्तर बायसंस तथा बिलासपुर बुल्स के मध्य खेला गया। बिलासपुर बुल्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय किया। बस्तर बायसंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुये 18.2 ओवरों में 10 विकेट खोकर केवल 112 रन बनाये। बस्तर बायसंस की शुरुवात काफी खराब रही, उनके प्रारंभिक बल्लेबाज 17 रन पर पवेलीयन लौट गये। उसके बाद निरंतर अंतराल में विकेट गीरते रहे। बस्तर बायसंस की ओर से अब्दुल अनस खान ने 29 रन तथा अमय मोरे ने 19 रन बनाये। बिलासपुर बुल्स की ओर से रुद्र प्रताप देहारी तथा मोहित राउत ने 3-3 विकेट प्राप्त किये, जिसमें मोहित राउत की शानदार हैट्रिक भी सम्मिलित है।

केवल 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिलासपुर बुल्स रने 15.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर 113 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लीया एवं फायनल में प्रवेश किया। बिलासपुर बुल्स की ओर से विकल्प तिवारी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुये 53 रन नाबाद बनाये। उनके अतिरिक्त अभिजीत ताह ने 22 रन तथा आयुष पांडेय ने 21 रनों का योगदान दिया। बस्तर बायसंस की ओर से देव आदित्य सिंह ने 2 विकेट प्राप्त किया। बिलासपुर बुल्स ने 7 विकेट से मैच जीत लिया एवं फायनल में प्रवेश किया। बिलासपुर बुल्स ने सीसीपीएल इतिहास में दूसरी बार फायनल में प्रवेश किया। मोहित राउत प्लेयर ऑफद मैच रहे।

116 रनों पर सिमटी रायपुर की पूरी टीम

शुक्रवार को दूसरा सेमी फायनल मैच रायगढ लायंस तथा रायपुर रायनोस के मध्य खेला गया। रायगढ लायंस ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय किया। रायपुर रायनोस ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर केवल 116 रन बनाये। रायपुर रायनोस की ओर से रायपुर रायनोस के केवल 3 बल्लेबाज दहाई का आंकडा पार कर सके। रायपुर रायनोस की ओर से मयंक यादव ने सर्वाधिक 46 रन, शाहबान खान ने 31 रन तथा वैभव साहु ने 24 रनो का योगदान दिया।

रायगढ लायंस ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुये रायपुर को बडा स्कोरब नाने से रोके रखा। रायगढ लायंस की ओर से आयुष सिंह ठाकुर ने हैट्रीक विकेट के साथ कुल 5 विकेट प्राप्त किये। 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रायगढ लायंस ने 14 ओवरों में 1 विकेट खोकर 117 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। रायगढ लायंस की ओर से संगीत सोनी ने नाबाद 50 रन तथा ऋषभ तिवारी ने 40 रन बनाये। रायगढ लायंस ने 9 विकेट से मैच जीत लिया। हैट्रिक के साथ कुल पांच विकेट लेने वाले आयुष सिंह ठाकुर प्लेयर ऑफद मैच रहे।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे नामांकन

रायपुर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2027 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों हेतु 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर योग्य एवं पात्र व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने भी सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और नागरिकों से ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है, जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल, लोक प्रशासन या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय और विशिष्ट योगदान दिया हो। नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं मापदंडों के अनुरूप तैयार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

स्ट्रीट वेंडर्स को 15-50 हजार रुपये तक ऋण सुविधा,18 जून को स्वनिधि कैंप

रायपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत कोरिया जिले में पथ विक्रेताओं के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून 2026 तक चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत 18 जून को नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में स्वनिधि कैंप का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तरुण कुमार एक्का ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य पथ विक्रेताओं, शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। कैंप में पात्र हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 हजार रुपये, 25 हजार रुपये तथा 50 हजार रुपये तक के चरणबद्ध ऋण के लिए आवेदन की सुविधा दी जाएगी।

हौसलों की उड़ानः संघर्षों को मात देकर 'लखपति दीदी' बनीं कांति साहू

रायपुर। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर श्लखपति दीदीश् बन रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसी कई महिलाओं ने प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं और छोटी पूंजी की मदद से स्वरोजगार अपनाकर अपनी तकदीर बदली है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत चल रहा लखपति दीदी अभियान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। इसका सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण बनी हैं बैकुण्ठपुर विकासखंड के ग्राम तलवापारा की रहने वाली श्रीमती कांति साहू। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच कांति ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि आज वे गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। एक सामान्य कृषक परिवार से ताल्लुक रखने वाली कांति साहू हमेशा से खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनका यह सपना दबा हुआ था। करीब तीन साल पहले वह गांव की महिलाओं के साथ मिलकर शारदा महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं।

फिल्में समाज को संदेश देने का सशक्त माध्यम- राज्यपाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। फिल्में और डॉक्युमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। यह कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि आदिम युग से ही मनुष्य विभिन्न माध्यमों से अपने विचार और संदेश व्यक्त करता रहा है। समय के साथ नाटक, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल माध्यमों ने इस भूमिका को और व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब वे बस्तर की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं। इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को कला, संगीत, नाटक और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त डॉक्युमेंट्री फिल्मों छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिंताराम, हैप्पी बर्थडे और स्क्रीन के निर्माता-निर्देशकों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन संस्कृति विभाग के संचालक संजय कन्नौजे ने दिया। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक मनोज वर्मा ने किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, विभिन्न डॉक्युमेंट्री फिल्मों के निर्माता-निर्देशक कलाकार एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

फिल्में समाज में सकारात्मक बदलाव की सशक्त माध्यम हैं - मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में संस्कृति विभाग एवं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डॉक्यूमेंट्री फि ल्म निर्माताओं, कलाकारों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज की सोच, संस्कृति और संवेदनाओं को दिशा देने वाली सशक्त विधा हैं।

एक अच्छी फिल्म समाज में जागरूकता पैदा करती है और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय सिनेमा ने समय-समय पर सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों, त्याग और आत्मसम्मान की भावना को सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का गौरवशाली इतिहास रहा है। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सार्थक संदेश दिया था। आज छालीवुड की फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के विस्तार से फिल्मों की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हुई है, ऐसे में जिम्मेदार, सकारात्मक और मूल्याधारित सिनेमा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को नई पहचान दिलाने और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम को पुनः सक्रिय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष जनवरी में 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का भूमिपूजन किया गया है। इस परियोजना से राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, हजारों कलाकारों, तकनीशियनों एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा फिल्म पर्यटन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम एवं संस्कृति विभाग को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और सिनेमा को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सराहनीय पहल है। ऐसे सम्मान समारोह कलाकारों और रचनाकारों का मनोबल बढ़ाने के साथ नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में 11 देशों में सम्मानित छत्तीसगढ़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ का भीम - चिंताराम का विशेष प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर उन्होंने गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र स्थित गिधनी पाठ में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये तथा धमतरी में सेन समाज भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा की। सर्व सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत सेन, वरिष्ठ फिल्म निर्माता मोहन सुंदरानी, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक, कलाकार एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रेशम, खादी और हथकरघा क्षेत्र को नई दिशाः केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनकरों, शिल्पियों एवं कारीगरों को डिजाइन विकास संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े तथा उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, छत्तीसगढ़ माटी कला एवं हस्तशिल्प बोर्ड के प्रबंध संचालक जयप्रकाश मौर्य, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती लीना कमलेश मंडावी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों को निर्यात एजेंसियों से जोड़ा जाए तथा उनके उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके। बैठक में सिल्क एवं कॉटन उत्पादों में अन्य प्राकृतिक रेशों के समावेश के माध्यम से नवीन उत्पाद विकसित करने तथा बाजार विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने रेशम केंद्रों में रेशम पौधों के साथ फ्लोरीकल्चर एवं सब्जी उत्पादन की मिश्रित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, जिससे कृमिपालकों एवं कीटपालकों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हो सके।

उन्होंने वस्त्र निर्माण में प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए हल्दी, कत्था, मेहंदी तथा विभिन्न पुष्पों से प्राप्त रंगों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता बताई। साथ ही हथकरघा क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक डिजाइन एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के सहयोग से कार्य करने के निर्देश भी दिए।

स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को मिली नई उड़ानः छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि **(PM SVANidhi)** योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय, नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक, कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, जूता-चप्पल विक्रेता, किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता, फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता, नाई, मोची, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी, जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है।

इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में हजारों पथ विक्रेता इस योजना के सहारे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वास्तव में उन मेहनतकश हाथों को आर्थिक संबल देने का माध्यम बनी है, जो अपने परिश्रम से शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

राज्य सरकार की सेवा सेतु केंद्र योजना से नागरिक सेवाएं हुईं आसान और सुलभ

सेवा सेतु केंद्र बना आमजनों के लिए सहारा, तत्काल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मिलने से रामेश्वरी ने जताया आभार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्रों और नागरिक सेवाओं का लाभ अब लोगों को एक ही स्थान पर आसानी से मिल रहा है। सेवा सेतु केंद्रों में सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।

ऐसी ही बस्तर जिले की एक हितग्राही रामेश्वरी ने मई माह में विवाह पंजीयन आवेदन किया था, सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि विकासखंड बस्तर के ग्राम चोकर निवासी तिरपती से फ़रवरी माह में विवाह हुआ था। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर वे सेवा सेतु केंद्र

पहुंचीं, जहां निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कुछ ही दिनों में ही प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। पहले इस प्रकार के कार्यों के लिए कई कार्यालयों में जाना पड़ता था और समय भी अधिक लगता था, लेकिन अब सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।

रामेश्वरी ने कहा कि सेवा सेतु केंद्र में उन्हें कर्मचारियों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन भी मिला और बिना किसी परेशानी के उनका कार्य पूरा हो गया। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को काफी सुविधा मिल रही है। उन्होंने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने के लिए शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन संबंधी राजपत्र अधिसूचना तथा भू-नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा सेतु पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु ने नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी मानी जा रही है। इससे आम लोगों का शासन व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है।

पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं। इनमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का एकीकरण भी किया गया है। तीस से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी है। पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से संचालित केंद्रों में शासन के कुछ ही सेवाएं उपलब्ध थी अब राज्य सरकार ने सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन सहित विभिन्न नागरिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे शासन की जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है।

अब अचियम्मा की तैयारी में जुटी जाह्नवी

जाह्नवी कपूर इस वक्त राम चरण की फिल्म पेड्डी से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इस फिल्म में उन्होंने अचियम्मा नाम की एक गांव की लड़की का किरदार निभाया है। यह देवरा (2024) के बाद साउथ में उनकी दूसरी फिल्म है। ताजा जानकारी है कि जाह्नवी अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर चुकी हैं। वह एक हाई-कॉन्सेप्ट हॉरर फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं, जिसका निर्देशन तुम्बाड वाले राही अनिल बर्वे करेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हॉरर फिल्म के लिए जाह्नवी और निर्माताओं के बीच बातचीत अंतिम चरण में हैं। सूत्र ने कहा, जाह्नवी कपूर फिलहाल अपनी अगली फिल्म के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। संभावित परियोजनाओं पर चर्चा कर रही हैं।

उन्होंने राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। तैयारियों का काम पहले ही शुरू हो चुका है और निर्माता इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।

सूत्र ने आगे कहा, जाह्नवी के लिए यह एक बिलकुल नया किरदार है और इसके लिए व्यापक तैयारी की जरूरत है। वह जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी। फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर निर्मित क्रिएचर हॉरर के रूप में चल रहा है। इसे जियो स्टूडियोज का समर्थन प्राप्त होगा।

शूटिंग इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। जाह्नवी लग जा गले में नजर आएंगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य भी हैं। यह 14 मई, 2027 को रिलीज होगी।

'प्रणित मोरे के शो भी बंद होने चाहिए'

रश्मि देसाई ने प्रणित मोरे के 370 बिरयानी विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वायरल बातचीत को कॉमेडी नहीं बताया और कहा कि इसमें क्रिएटिविटी की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद से कॉमेडी जगत को नुकसान हो रहा है और प्रणित को भी इसके नतीजे भुगतने चाहिए।

370 बिरयानी विवाद पर कॉमेडियन पर भड़कीं एक्ट्रेस रश्मि देसाई

टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने कॉमेडियन प्रणित मोरे के चल रहे '370 की बिरयानी' विवाद पर रिएक्शन दिया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, रश्मि ने कंटेंट क्रिएटर प्रफुल्ल गर्ग की एक पोस्ट शेयर की। प्रफुल्ल ने प्रणित की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने क्राउडवर्क के दौरान एक ऐसी बातचीत में हिस्सा लिया और हंसे, जिसे कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना। वायरल क्लिप की आलोचना तब हुई जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की, जिसे व्यापक रूप से एक महिला की सहमति को पैसे के लेन-देन के बराबर मानने के तौर पर देखा गया। हालांकि, रश्मि ने प्रणित के व्यवहार की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ऐसी बातचीत को सामान्य बातचीत भी बताया और कहा कि लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी की कमी होती है।

रश्मि देसाई ने क्रिएटर को लताड़ लगाते हुए लिखा, प्रफुल्ल भाई, यह कॉमेडी नहीं है। यह सामान्य बातचीत है और इसमें कोई कंटेंट नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो वे ऐसी बातचीत करने लगते हैं।

इसके बाद रश्मि ने प्रणित की आलोचना करते हुए अपनी बात रखते हुए लिखा, प्रणित कलाकार नहीं है। वो कॉमेडियन भी नहीं है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से कॉमेडी जगत की अनावश्यक आलोचना हो रही है और यह सच्चे कलाकारों के लिए बहुत बुरा है। उन्होंने कहा, इस इंडस्ट्री को बेवजह ट्रोल किया जाएगा, ये वास्तविक कलाकारों के लिए बुरा है।

प्रणित मोरे के भी शो बंद होने चाहिए

प्रणित के शो के दौरान विवादित टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा के बारे में बात करते हुए, रश्मि ने बताया कि आलोचना के बीच कथित तौर पर उनकी नौकरी चली गई थी। एक्ट्रेस ने तर्क दिया कि अगर उसे अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़े हैं, तो प्रणित को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, और इस लड़के की नौकरी चली गई है। साथ ही, प्रणित के भी शो बंद होने चाहिए।

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, shame-onpranit SHAME ON GURGAON BOY.. बढ़ते विरोध के बीच, प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक्सेस नहीं हो पा रहा था, जिससे इस विवाद को और हवा मिली। हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कॉमेडियन ने खुद अकाउंट डीएक्टिवेट किया या रिपोर्ट किए जाने के बाद उसे हटा दिया गया। बता दें कि इस घटनाक्रम पर रिएक्शन देते हुए, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि प्रणित आलोचना से भाग गए हैं, जबकि दूसरों का तर्क था कि उनके खिलाफ ऑनलाइन विरोध बहुत ज्यादा हो गया था।

धक-धक गर्ल की फिल्म देख फैन हुई देसी गर्ल

प्रियंका चोपड़ा ने 'मां बहन' पर लुटाया प्यार

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने माधुरी दीक्षित की नई फिल्म मां-बहन को लेकर अपनी राय साझा की है। देसी गर्ल ने क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने दर्शकों के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों का भी दिल जीत लिया है। तीन महिलाओं की कहानी और समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारने वाली फिल्म 'मां बहन' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब इस फिल्म की तारीफ करने वालों की सूची में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने खास तौर पर माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और कंटेंट क्रिएटर से अभिनेत्री बनीं धर्ना दुर्गा के अभिनय की सराहना की। प्रियंका ने फिल्म को मनोरंजन और सामाजिक मैसेज का शानदार मिश्रण बताया। उन्होंने लिखा- सच ए क्लेवल फिल्म। शार्प, फनी एंड सो वेल डन।

प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा कि फिल्म को इतने शानदार और प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने धर्ना दुर्गा के काम की खास प्रशंसा करते हुए कहा कि वो पहले से ही उनकी फैन रही हैं और भविष्य में उनके नए प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगी। फिल्म में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की दमदार मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। दोनों कलाकारों ने अपने किरदारों में भावनात्मक गहराई और मनोरंजन का संतुलन बनाए रखा है। यही वजह है कि फिल्म रिलीज के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का निर्देशन करने वाले निर्देशक की भी काफी तारीफ हो रही है। इसके अलावा फिल्म में कंटेंट क्रिएटर धर्ना दुर्गा भी पहली बार एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें फिलहाल ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में एक सिंगल मां की कहानी दिखाई गई है जिसकी दो बेटियां हैं। समाज किस नजर से तीन अकेली महिलाओं को देखता है, बस कुछ इसी के ईर्द-गिर्द फिल्म की कहानी को बुना गया है।

'अलग ही तहजीब और चमक'

कंगना रनौत की पोस्ट पर फैंस कर रहे तारीफ, 'भारत भाग्य विधाता' का है इंतजार

एक्ट्रेस कंगना रनौत की ने सोशल मीडिया कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। फैंस उनकी सादगी, तहजीब और परसनैलिटी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, प्रशंसक उनकी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

जल्द ही बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भारत भाग्य विधाता रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्ससाइटमेंट है।

वहीं, कंगना रनौत इन दिनों अपनी इस फिल्म के प्रचार-प्रसार में काफी व्यस्त भी हैं। इसी बीच कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिन पर उनके फैंस भर-भर कर कमेंट्स कर रहे हैं।

अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोजस शेयर की हैं, जिनमें वो ऑरेंज कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने हुए हैं। बता दें कि ये फोटोज भी उन्होंने भारत भाग्य विधाता फिल्म के प्रमोशन इवेंट के लिए ही पहनी है।

क्वीन एक्ट्रेस के इस लुक पार उनके फैंस फिदा हो गए हैं। कुछ यूजर्स जहां उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, कि आपकी फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है।

एक यूजर ने लिखा, 'एक अलग ही तहजीब और चमक। 12 जून को सिनेमाघरों में एक्ट्रेस कंगना रनौत का जलवा देखने का इंतजार!'

दो दिन बाद रिलीज होने वाली है 'भारत भाग्य विधाता'

बता दें कि हाल ही में कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी की भावुक झलक दिखाई गई है।

वो कहानी जो उन आम लोगों के बारे में है जिन्होंने मुश्किल और डरावने समय में असाधारण हिम्मत दिखाई और 400 से ज़्यादा लोगों की जान बचाने में मदद की। 'भारत भाग्य विधाता' उन नर्सों और वार्ड बॉयज की कहानी दिखाती है जो देश के सबसे मुश्किल दौर में गुमनाम हीरो बनकर सामने आये।

नर्सों की यूनिफॉर्म पर बयान देकर फंसी कंगना रनौत

कंगना ने कहा, मुझे लगता है कि ब्रिटिश नर्सों वाला ड्रेस कोड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नर्सें, डॉक्टरों की तरह, जो चाहें पहन सकती हैं; उन्हें एक कोड मिलता है। लेकिन हमारी नर्सें, चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, एक तरह से विदेशी लुक में दिखती हैं। यह मेरी निजी राय है। लेकिन इस फिल्म में हमने ईमानदारी और सम्मान के साथ काम किया है। आकार और साइज़ मायने नहीं रखता, आपकी यूनिफॉर्म ही आपकी ड्यूटी है।

हालांकि, इस बयान के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया।

टमाटर से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

टमाटर एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल सलाद में बल्कि कई स्वादिष्ट व्यंजनों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। टमाटर में विटामिन-सी, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। आइए हम आपको टमाटर से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। इन व्यंजनों को बनाना भी आसान है और ये आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।

टमाटर का हलवा

टमाटर का हलवा एक खास और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर घी में सूजी भूनें और उसमें टमाटर का पेस्ट मिलाएं।

इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है। इसे आप किसी खास मौके पर बना सकते हैं या किसी भी समय मिठाई के रूप में परोस सकते हैं।

टमाटर का पुलाव

टमाटर का पुलाव एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर तेल या घी में जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी डालकर भूनें। अब कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें, फिर कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं जब तक वे नरम हो जाएं। इसके बाद भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।

टमाटर का रायता

गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता कौन नहीं पसंद करता? टमाटर का रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और हरी मिर्च डालकर मिलाएं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। इसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। यह रायता न केवल आपके खाने को ताजगी देता है बल्कि आपके पेट को भी शांत रखता है।

टमाटर की कढ़ी

पंजाबी कढ़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी टमाटर की कढ़ी चखी है? अगर नहीं तो आज ही आजमाएं। इसके लिए बेसन के घोल में मसाले मिलाकर छोटे-छोटे पकौड़े बना लें, फिर पानी उबालकर उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च मिलाकर पकाएं। अब इन पकौड़ों को इसमें डालकर पकाएं। दूसरी तरफ टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर मिलाएं। अंत में दोनों को मिलाकर परोसें।

टमाटर की चटनी

दाल-चावल या परांठे किसी भी व्यंजन के साथ परोसने लायक यह चटनी बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्तियां और नींबू रस मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को कटोरे में निकालकर उसमें नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा तेल डालें। आपका स्वादिष्ट टमाटर की चटनी तैयार है। इसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।

खास खबर

सूरज की रोशनी से चमका राजनांदगांव, सोलर ऊर्जा का बना राष्ट्रीय मॉडल

रायपुर। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने उसे देशभर में नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के बल पर राजनांदगांव देश में सर्वाधिक सोलर क्षमता वाले कनेक्शन स्थापित करने वाला जिला बन गया है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी सौर ऊर्जा को लेकर लोगों का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन तथा विद्युत विभाग के समन्वित प्रयासों से यह सफलता संभव हुई है। योजना के तहत जिले में अब तक 6776 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6381 हितग्राहियों ने वेंडर का चयन कर लिया है। वहीं 3255 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं और 2218 लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान भी किया जा चुका है। जिले में 3255 घरेलू सोलर कनेक्शनों के माध्यम से लगभग 9 मेगावाट, 162 व्यावसायिक सोलर कनेक्शनों से 3.40 मेगावाट तथा 31 पावर प्लांटों के जरिए 383 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि ढाबा स्थित मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफइंडिया लिमिटेड के 160 मेगावाट क्षमता वाले सोलर कनेक्शन की है, जो देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है।

हल्दी-अदरक की खेती के लिए 49,800 रुपये तक अनुदान

रायपुर। मसाला फसलों के रकबे को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विभाग बालोद ने खरीफवर्ष 2026-27 के लिए हल्दी और अदरक की खेती पर आकर्षक अनुदान देने की घोषणा की है। राज्यपोषित मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर लाभ दिया जाएगा। उद्यानिकी विभाग के अनुसार जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी तथा 33 हेक्टेयर क्षेत्र में अदरक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी शासकीय उद्यान रोपणी या उद्यानिकी कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि प्रमाणित एवं आधार बीज के उपयोग पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। हल्दी की खेती में प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल बीज उपयोग करने पर 47 हजार रुपये तथा अदरक की खेती में प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल बीज लगाने पर 49 हजार 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। विभाग ने किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

सड़कों से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ेंगे बच्चे, जिले में विशेष अभियान शुरू

बलौदाबाजार। राज्य शासन द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में बाल सक्षम नीति-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने 9 जून को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सड़क पर रहने वाले, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम तथा अपशिष्ट संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू, पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर शर्मा के निर्देश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन और जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग,विशेष अभियान चलाया।

हर वर्ग की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, तेज गति से दौड़ रहा है छत्तीसगढ़ का विकासः मंत्री टंक राम वर्मा

बलौदाबाजार को 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातः राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया भूमिपूजन और लोकार्पण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र को करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मंत्री वर्मा ने कुल 3 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया, साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 12.32 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित रैन बसेरा का लोकार्पण भी किया।

भूमिपूजन एवं लोकार्पण के इन विकास कार्यों पर नजर डालें तो नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत वार्ड क्रमांक 16 में 56.86 लाख रुपए की लागत से 12 नग राहत शिविरों का निर्माण किया जाएगा, वहीं वार्ड क्रमांक 12 में भी 60.25 लाख रुपए की राशि से 10 नग राहत शिविरों की आधारशिला रखी गई है। स्थानीय नागरिकों की संवेदनशीलता और जरूरत को देखते हुए वार्ड क्रमांक 17 में 61.44 लाख रुपए खर्च कर मुक्तिधाम का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

इसी तरह शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए अधिसंरचना एवं पर्यावरण निधि के अंतर्गत 1.17 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे विभिन्न वार्डों में 10 अलग-अलग विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही, आम जनता को स्वच्छ और सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग-अलग क्षेत्रों में 40.72 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन विस्तार का कार्य शुरू किया गया है। इन सभी भूमिपूजन कार्यों के साथ-साथ, सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए बस स्टैंड के पास विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए 12.32 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक रैन बसेरे का निर्माण पूरा कर उसका लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को पूरी गति के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गाँव हो या शहर, विकास की राह में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

हमारी डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास के पथ पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। युवा, महिला, किसान और बुजुर्ग—हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं और जनता इनका सीधा लाभ उठाकर खुशहाल है। भूमिपूजन कार्यक्रम के पश्चात मंत्री वर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने पास में स्थित डबरी (तलाब) की मेढ़ पर आंवले का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में नीम का पौधा भी रोपा।

इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारी उपस्थित थे।

बेहतर समन्वय और सहयोग से शहर के विकास व स्वच्छता के लिए करें कार्य : शंगीता आर.

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने आज राजनांदगांव जिला मुख्यालय में शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि नगरीय प्रशासन को बेहतर बनाना और शासन की योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन कराना अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। नगरीय निकायों में अलग-अलग वार्डों के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि सभी नोडल अधिकारी समग्र दृष्टिकोण से अपने संबंधित वार्ड एवं क्षेत्रों के संबंध में पूरी जानकारी रखें एवं कार्यों की नियमित मानिटरिंग करें। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और राजनांदगांव के कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव भी बैठक में शामिल हुए।

श्रीमती शंगीता आर. ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी बजट का सदुपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने राजनांदगांव नगर निगम तथा जिले के अन्य नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सक्रियता, ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर आपसी समन्वय और सहयोग से टीम वर्क के साथ शहर के विकास व स्वच्छता के लिए कार्य करने को कहा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव ने बैठक में कहा कि बारिश के दिनों में ऐसे स्थान जहां जल भराव की स्थिति बन सकती है, उनका चिन्हांकन करते हुए बारिश के पहले सभी नालियों की साफ-सफाई कराएं। बरसात में पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवासों के आधिपत्य एवं हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा उनकी जियो-टैगिंग के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों के छत, प्लिंथ और फाउंडेशन के कार्य बारिश के पहले पूर्ण करने को कहा। उन्होंने मकान स्वीकृति के सत्यापन का कार्य भी शीघ्र करने को कहा। सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने शहरों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और अमृत मिशन 2.0 के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बिल के भुगतान एवं अन्य कार्यों के लिए नगराय निकायों में आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशीलता से सभी सफाई कर्मियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने नालंदा परिसर के निर्माण में गति लाने के भी निर्देश दिए। राजनांदगांव जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा और नगरीय प्रशासन विभाग के दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक जय प्रकाश साहू सहित राजनांदगांव जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अभियंता एवं नोडल अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

दिव्यांग मनुराज को मिला संबल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से अब शिक्षा की राह होगी आसान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सुशासन तिहार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बना है। कबीरधाम जिले के पण्डरिया तहसील के ग्राम मोंहगांव निवासी 85 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग मनुराज बंजारे को आवेदन करने पर बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदान की गई।

ट्रायसायकल मिलने से अब उनके लिए आवागमन आसान हुआ है और लंबे समय से अधूरी रह गई शिक्षा तथा आत्मनिर्भर बनने के सपनों को नई दिशा मिली है। यह सहायता उनके लिए केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का सशक्त माध्यम बनी है। मनुराज बंजारे 85 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग हैं। उन्होंने सुशासन तिहार 2026 के दौरान बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके आवागमन में अब काफी सहजता आएगी। इन परिस्थितियों के चलते वे मानसिक रूप से भी काफी परेशान और निराश रहने लगे थे। लेकिन अब बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल मिलने से उनके जीवन में एक नई आशा आई है। मनुराज बंजारे ने कहा कि अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और वे अपनी अधूरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

22 ग्राम पंचायतों में लगी कृषक चौपाल, प्राकृतिक खेती पर जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। 'खेत बचाओ अभियान' के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए महासमुंद जिले की 22 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल एवं कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। अभियान 30 जून तक संचालित किया जाएगा।

कृषि विभाग के अनुसार विकासखंड महासमुंद की 5 ग्राम पंचायतों, बसना की 8, पिथौरा की 2 और सरायपाली की 7 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। चौपालों में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने किसानों को बताया कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रमों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक खेती के लाभ, हरी खाद, नील हरित काई तथा जैविक उत्पादों के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी, जैव उर्वरक, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैविक खाद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

अधिकारियों ने किसानों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की, ताकि खेती अधिक टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बन सके।

छत्तीसगढ़ को मिला पहला संभागीय पोर्टल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सरगुजा संभाग अब राज्य का पहला ऐसा संभाग बन गया है, जिसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो गई है। संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को https//division-surguja.cg.gov.in/ पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरगुजा द्वारा विकसित यह वेबसाइट केंद्र सरकार के सुरक्षित SxWaaS प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। आधुनिक तकनीक से लैस पोर्टल 'सिक्योर बाय डिजाइन' फ्रेमवर्क पर आधारित है तथा इसकी होस्टिंग एनआईसी के नेशनल डाटा सेंटर में की गई है। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर सहजता से संचालित होगी।

पोर्टल के माध्यम से नागरिक सरगुजा संभाग की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, अधिकारियों की संपर्क सूची और सभी जिलों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

साथ ही बी-1/पी-11, नामांतरण, राजस्व न्यायालय आवेदन और डायवर्जन जैसी ऑनलाइन राजस्व सेवाओं तक भी सीधी पहुंच मिलेगी। संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि सभी जिलों और एनआईसी टीम के सहयोग से तैयार यह पोर्टल प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करेगा तथा डिजिटल प्रशासन का नया मानक स्थापित करेगा।

रासायनिक उर्वरकों की दरें तय

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय दर से अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि यूरिया की कीमत 266.50 रुपये प्रति बोरी निर्धारित की गई है। डीएपी उर्वरक कंपनी के अनुसार अधिकतम 1350 रुपये प्रति बोरी तक उपलब्ध होगा। वहीं एनपीके 12:32:16 की कीमत 1190 रुपये, 20:20:0:13 की 1850 रुपये और 12:26:26 की 1990 रुपये प्रति बोरी तय की गई है। एमओपी (पोटाश) उर्वरक 1975 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलेगा।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक संपन्न

छत्तीसगढ़ जनहितैषी योजनाओं के लोन प्रकरणों को जल्द स्वीकृत करें बैंकर्स

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक तेजी से पहुंचाने के लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनहित की योजनाओं से जुड़े ऋण (लोन) और अनुदान (सब्सिडी) के मामलों को बैंकर्स बिना किसी देरी के जल्द से जल्द स्वीकृत करें।

बैठक में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत 31 मार्च तक बैंकों द्वारा दिए गए लोन और वित्तीय सहायता के मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के 31 मार्च तक के हितग्राहियों को बैंकों द्वारा प्रदत्त लोन एवं अन्य वित्तीय सहायता के प्रकरणों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के आवेदनों को बेवजह लंबित न रखा जाए। फाइलों के त्वरित निपटारे के लिए उन्होंने बैंकर्स को एक व्यावहारिक व्यवस्था बनाने को कहा है।

बैंकर्स से कहा गया है कि वे स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रति सप्ताह एक निर्धारित दिन (फिक्स्ड डे) तय करें, ताकि उसी दिन सभी आवेदनों की जांच कर उनका तत्काल निपटारा किया जा सके।

इस उच्च स्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न राष्ट्रीयकृत व क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शासन की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आम नागरिकों और ग्रामीण उद्यमियों को बैंकों से ऋण मिलने की प्रक्रिया बेहद सुगम और पारदर्शी हो जाएगी।

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

स्कूटी में भरकर ले जा रहे थे 15 किलो गांजा, दो तस्कर गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूटी से गांजा तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बोधघाट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक एक्टिवा स्कूटी से गांजा लेकर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में बोधघाट पुलिस और ब्लैक पैथर टीम ने लामनी रोड पर घेराबंदी कर जांच अभियान शुरू किया। रेड कार्रवाई के दौरान संदिग्ध एक्टिवा को रोककर तलाशी ली गई। जांच में स्कूटी सवार दो युवकों के बैग से 15.110 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख 55 हजार 500 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील कश्यप (28 वर्ष) निवासी नानगुर और सागर कश्यप (22 वर्ष) निवासी नेगीगुड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से गांजे के अलावा एक एक्टिवा स्कूटी, दो मोबाइल फोन और 1100 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी गांजा परिवहन और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

परेशानी दूर करने का झांसा देकर व्यापारी से 3 लाख की ठगी

बिलासपुर। व्यापार विहार में खरीदारी करने आए एक व्यापारी को अंधविश्वास का झांसा देकर शातिर बदमाशों ने तीन लाख रुपये से भरा बैग पार कर दिया। नवागढ़ निवासी जनकराम साहू शुक्रवार दोपहर अपने बेटे उमेश साहू के साथ लहसुन और मिर्च की खरीदारी के लिए व्यापार विहार पहुंचे थे। खरीदारी में सुविधा के लिए पिता-पुत्र अलग-अलग दुकानों की ओर चले गए। इसी दौरान जनकराम साहू के पास दो अज्ञात युवक पहुंचे और बातचीत शुरू कर दी। बदमाशों ने व्यापारी को विश्वास में लेते हुए दावा किया कि वे उसकी परेशानियां दूर कर सकते हैं। झाड़-फूंक और पूजा-पाठ के नाम पर उन्होंने ऐसा जाल बुना कि व्यापारी उनकी बातों में उलझ गया। इसी बीच मौका पाकर शातिरों ने तीन लाख रुपये से भरा बैग गायब कर दिया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ तो उसने आसपास के लोगों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वे आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना की सूचना मिलने पर तारबाहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

नशेड़ी ड्राइवरो पर सख्तीः रायपुर में इस साल अब तक 3000 से ज्यादा चालकों पर कार्रवाई

एक ही रात में पकड़े गए 52 वाहन चालक, यातायात पुलिस ने वसूला हजारो का जुर्माना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। वर्ष 2026 में अब तक रायपुर पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 3365 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। वर्ष 2026 में अब तक रायपुर पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 3365 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसी अभियान के तहत 7 जून की रात शहर के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 52 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए। इनमें 34 कार चालक, 11 बाइक सवार, 4 ट्रक चालक, 2 टाटा एस वाहन चालक और 1 पिकअप वाहन चालक शामिल हैं।

9 प्रमुख स्थानों पर हुई विशेष जांच

यातायात पुलिस की टीमों ने तेलीबांधा चौक, पचपेड़ी नाका, भाठागांव चौक, टाटीबंध चौक, कालीबाड़ी चौक, जयस्तंभ चौक, भनपुरी चौक और पंडरी थाना क्षेत्र सहित शहर के नौ स्थानों पर देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर की मदद से वाहन चालकों की जांच की गई, जिसमें कई लोग निर्धारित सीमा से अधिक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले। पकड़े गए सभी चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करेगी, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की कवायद

यातायात पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजहों में से एक है। ऐसे में लगातार अभियान चलाकर लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने और कानून का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी शहरभर में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

नागरिकों से की गई अपील

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। साथ ही अभिभावकों से नाबालिगों को वाहन नहीं देने की सलाह दी गई है। पुलिस का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल कानून लागू करने से नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी और जागरूकता से भी सुनिश्चित होती है। इसलिए सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नशे के कारोबार पर पुलिस का बड़ा प्रहार

96 घंटे के ऑपरेशन में 8 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और विभिन्न थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 96 घंटे के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान हेरोइन, एमडी ड्रग्स, गांजा, नशीली टेबलेट, नकदी और मोबाइल फोन समेत करीब 5 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान टिकरापारा, सिविल लाइन, न्यू राजेंद्र नगर, खमतराई और डीडी नगर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भाठागांव स्थित नए बस स्टैंड के आसपास हेरोइन की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से 8.75 ग्राम हेरोइन और बिक्री की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अफसर कादर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

खमतराई क्षेत्र में एक विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से 1.8 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक अन्य कार्रवाई के दौरान 1.2 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अलग कार्रवाई के दौरान एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को 40 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक नारकोटिक्स एक्ट के 49 मामलों में 113 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन मामलों में 2.63 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की गई है।

दो बोरियों में बंधी मिली युवक की लाश हत्या की आशंका से फैली सनसनी

श्रीकंचनपथ न्यूज

सूरजपुर। जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तीवरागुड़ी सरनापारा में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के बाहरी हिस्से में बिजली खंभे के पास रखी दो संदिग्ध बोरियों से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

ग्रामीणों ने सुबह खंभे के पास पड़ी बोरियों को देखा। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर जब लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बोरियों के भीतर एक व्यक्ति का शव बंधा हुआ था। घटना की सूचना तत्काल गांव के पूर्व सरपंच और पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी मौके पर बुलाया। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के साथ पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिसके चलते पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों का भी मिलान कर रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और कर शव को पहचान छिपाने की नीयत से बोरी में भरकर यहां फेंका गया हो सकता है।

फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। इस रहस्यमयी वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना दिया है।

कोयला चोरी और मिलावट के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। सकरी पुलिस ने कोयला चोरी एवं मिलावट के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए अपराध दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर कोयला परिवहन के दौरान कथित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की चोरी कर उसमें मिलावट करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार न्यू लोको कॉलोनी, मरहीमाता मंदिर बिलासपुर निवासी आर.के. पाण्डेय ने थाना सकरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि दीपका कोल माइंस से भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, लोखंडी के लिए एफजी ग्रेड का कोयला मंगवाया गया था। 10 जून की सुबह जब कोयले से लदे तीन ट्रेलर प्लांट पहुंचे और लेबोरेटरी में जांच की गई, तब कोयला निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया।

शिकायत के बाद ट्रेलर चालकों से

पूछताछ की गई, जिसमें कथित रूप से यह तथ्य सामने आया कि एफ ग्रेड कोयले की चोरी कर उसमें मिलावट की गई थी। मामले में बालाजी कोल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन के संचालक तथा प्लांट के सुपरवाइजर की मिलीभगत से साजिश रचकर कोयला चोरी किए जाने की बात सामने आई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी ने विशेष टीम गठित की। एसीसीयू एवं माइनिंग विभाग के सहयोग से कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में आशिक हुसैन अंसारी, फैजान रजा अंसारी और फुजैल अंसारी निवासी जिला गढ़वा (झारखंड), गौरव राजपूत एवं सीबु खान निवासी बिलासपुर तथा दिलीप कुमार यादव निवासी भिलाई, जिला दुर्ग शामिल हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है तथा कोयला चोरी और मिलावट से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

इस कार्रवाई में थाना सकरी पुलिस, एसीसीयू टीम तथा माइनिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महिला की हत्या का खुलासा : प्रेम संबंध में विवाद के बाद देवर ने उतारा मौत के घाट

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलौदाबाजार। सिविल लाइन इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक 28 वर्षीय महिला की उसके ही घर के पीछे बाड़ी में खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई है, वह रिश्तों के टूटते भरोसे, प्रेम प्रसंग और खूनी अंजाम की दास्तान बयां कर रही है। मृतका की पहचान पुष्पा ध्रुव उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है।

महिला का शव घर के पीछे बाड़ी में पड़ा मिला। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और साइबर सेल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सूचना के बाद लगभग 4 बजे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए।

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर शक परिवार के ही एक सदस्य पर गया। पुलिस ने मृतका के देवर देवेंद्र ध्रुव उम्र 25 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका और उसके देवर के बीच पिछले करीब चार वर्षों से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच इस रिश्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पहले महिला को छत पर मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि वह नीचे पहुंचा और पास में रखी ईंट उठाकर महिला के सिर और चेहरे पर लगातार वार करता रहा। हमला इतना निर्मम था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर घटना वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसने विवाद को हत्या तक पहुंचा दिया। मोबाइल कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़ी जा सके. पुलिस पड़ोसियों और परिजनों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि हत्या से पहले और बाद की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

राजस्व मामले में नोटिस

न्यायालय न्यायालय तहसीलदार भिलाई-3
तहसील-भिलाई-3 जिला-दुर्ग
राजस्व प्रकरण क्रमांक 202605101600035

मामले का विषय -अ-6 अ (खसरे में अथवा धारा-114 के अधीन तैयार किये गये किसी अन्य भू अभिलेख संबंधी कागज में गलत प्रविष्टि का सुधार अथवा उनमें प्रविष्टी संबंधी विवाद)

पक्षकारों का विवरण-आवेदक पक्षकार-साथी सेन, अनावेदक पक्षकार -विकास कुसुम महंती,

भूमि का विवरण जिसके संबंध में विवाद विचाराधीन है जिला-दुर्ग तहसील-भिलाई-3 प.ह.नं.-00009 ग्राम-[खसरा (रकबा)] चरोदा

आवेदक/अनावेदक/गवाह जिसे नोटिस जारी किया जा रहा है

नाम-विकास कुसुम महंती पिता-जनार्दन महंती, पता-पुरुलिया, तहसील व जिला पुरुलिया (वेस्ट बंगाल) आपको सूचित किया जाता है की उपयुक्त मामले के सुनवाई की तारीख -24/06/2026 दिन के 11 बजे, स्थान: न्यायालय तहसीलदार भिलाई-3 पर होगी

विषय: आवेदक साथी सेन पति मानब सेन निवासी रामनगर नेताजी सुभाष रोड जहाज बिल्डिंग के पास रामनगर भिलाई जो ग्राम चरोदा, प.ह.नं. 09, रा.नि. मं. चरोदा तहसील भिलाई 03 जिला-दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 444/30 रकबा 0-032 हे. भूमि के भूमिस्वामी है किंतु आनलाईन रिकार्ड में भूमिस्वामी के नाम में विक्रेता विकास कुसुम महंती पिता-जनार्दन महंती का नाम प्रदर्शित हो रहा है उक्त त्रुटि को सुधार करने बाबत् आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

नोटिस दिनांक 11/06/2026

तहसीलदार
भिलाई - 3 जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

(ई-मेल- mandibemetara@gmail.com)

क्रमांक / मंडी / निर्माण / 2026-27 / 118 — बेमेतरा, दिनांक 05/06/2026

// निविदा आमंत्रण सूचना //

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) के अंतर्गत निम्न दर्शित कार्य/स्थल एवं कार्य के सम्मुख दर्शित लागत अनुसार कार्य कराये जाने हेतु छ.ग. लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं केवल पंजीकृत डाक से चार लिफाफा पद्धति से दिनांक 30.06.2026 दिन मंगलवार को सायंकाल 5.30 बजे तक छ.ग. शासन लो.नि.वि. सड़क कार्य हेतु दिनांक 01.01.2025 से प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं इस निविदा जारी दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर निविदा प्रपत्र-अ (प्रतिशत दर) में कार्यालय सचिव, कृषि उपज मंडी समिति-बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं इस कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों/प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 02.07.2026 दिन गुरुवार को दोपहर 03.00 बजे खोली जावेगी।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि :- 23.06.2026 को सायं 05.00 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 30.06.2026 को सायं 05.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र खोले जाने की प्रारंभिक तिथि :- 02.07.2026 को दोप. 03.00 बजे दोपहर से

क्र.	विधानसभा का नाम	कार्य का नाम / स्थल	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि रू. में	ठेकेदार की श्रेणी	समयावधि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साजा	ग्राम पलेमी में रमेश कोटवार के घर से पुलिया तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00
2	साजा	ग्राम पलेमी में महावीर चौक से दुर्गा चौक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00
3	साजा	ग्राम पंचायत केशतरा में हनुमान मंदिर के पास डोम शेड निर्माण।	9.57	7500=00	"द" एवं उच्च	6 माह	1000=00
4	साजा	ग्राम केशतरा में पंचायत भवन से अश्वनी साहू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00
5	साजा	ग्राम गड्डवा में पलटन कोटवार के घर से नवधा चौक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00
6	साजा	ग्राम गड्डवा में सामुदायिक भवन से चंडी मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00
7	साजा	ग्राम गड्डवा में चंडी मंदिर के पास डोम शेड निर्माण कार्य।	9.57	7500=00	"द" एवं उच्च	6 माह	1000=00
8	साजा	ग्राम गड्डवा में राजा पटेल के घर से शत्रु ठाकुर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.94	7500=00	"द" एवं उच्च	3 माह	1000=00

शर्तें:- 1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए वैध पंजीयन, बैंक साल्वेंसी (एक साल से पुराना न हो एवं अनुमानित लागत का 15 प्रतिशत की मूल्य का), जी.एस.टी. पंजीयन, श्रम कल्याण मंडल (ई.पी.एफ.) का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की मूलप्रति अक्लोकनार्थ तथा आवेदन सहित समस्त दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 23.06.2026 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क रू. 1000/- की नगद/डी.डी. जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। 2. अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर./टी.डी.आर. या डाक विभाग द्वारा एन.एस.सी. के रूप में "सचिव कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)" को देय ही स्वीकार्य होगा। 3. अन्य शर्तें एवं कार्य से संबंधित जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक 23.06.2026 तक देखें/प्राप्त किये जा सकते है, जो कि निविदा अनुबंध का अनिवार्य भाग है, एवं वरिष्ठालय के पत्र क्रमांक 4065 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा संलग्न अतिरिक्त शर्तें क्र. 10 एवं 11 इस निविदा शर्तों का भाग होगा।(सुलभ संदर्भ हेतु पत्र व शर्तें संलग्न है।) 4. इस आमंत्रित निविदा अनुसार उपरोक्त कार्यों के लिए निविदा दर प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन का परिपत्र क्र. 625/3675/टी/11/19 निविदा रायपुर दिनांक 05.03.2011 द्वारा प्रभावशील नियम लागू/प्रभावशील है। 5. उपरोक्त कार्य हेतु यदि निविदाकार द्वारा लागू दर/दर अनुसूची में 10 प्रतिशत से कम दर कोट किया जाता है तो निविदा हेतु स्पेशल शर्तें लागू होगी। तदानुसार अंतर की राशि "सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)" के नाम एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करना होगा। शर्तों की प्रति निविदाओं के साथ प्रदाय की जायेगी। 6. लिफाफा- "अ" में ई.एम.डी. एवं शपथ पत्र, लिफाफा- "ब" में समस्त दस्तावेज (वैध पंजीयन, श्रम कल्याण मंडल (ई.पी.एफ.) का पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी (एक साल से पुराना न हो एवं अनुमानित लागत का 15 प्रतिशत की मूल्य का), जी.एस.टी. पंजीयन, पेनकार्ड की मूलप्रति की छायाप्रति तथा लिफाफा- "स" में निविदा प्रपत्र एवं लिफाफा "द" में लिफाफा "अ", "ब" एवं "स" को भरकर प्रस्तुत किया जावेगा तथा लिफाफा "द" में कार्य क्रमांक एवं कार्य का नाम स्पष्ट उल्लेख करें।

S- 48142/3

हस्ता./सही
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

हस्ता./सही
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पत्थर से हमला कर युवक की हत्या के मुख्य आरोपी समेत चार गिरफ्तार

कोटा। चरित्र शंका के चलते एक युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर और सिर पर पत्थर से वार कर हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक दास उर्फ भोला दास मानिकपुरी, निखिल राव उर्फ निक्कू, करण दास मानिकपुरी और कुश साहू उर्फ बुतरू शामिल हैं। आरोपियों ने निखिल के सिर को पत्थर से कुचल दिया था और अत्यधिक खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

खास खबर

राष्ट्रीय जूडो में कोंडागांव की बेटी हेमबती ने जीता कांस्य

कोंडागांव। कोंडागांव की हेमबती नाग ने चंडीगढ़ में आयोजित ओपन नेशनल जूडो प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हेमबती बालिका गृह, कोंडागांव की खिलाड़ी हैं। उनकी सफलता न केवल कोंडागांव जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हेमबती को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों को शिक्षा, खेल और व्यक्तित्व विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हेमबती की सफलता प्रदेश की हजारों बेटियों के लिए प्रेरणादायी है और यह साबित करती है कि प्रतिभा किसी संसाधन या भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं होती।

छत्तीसगढ़ को मिला पहला संभागीय पोर्टल

रायपुर। डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सरगुजा संभाग अब राज्य का पहला ऐसा संभाग बन गया है, जिसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो गई है। संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को https://division-surguja.cg.gov.in/ पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। पोर्टल 'सिक्योर बाय डिजाइन' फ्रेमवर्क पर आधारित है तथा इसकी होस्टिंग एनआईसी के नेशनल डाटा सेंटर में की गई है। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर सहजता से संचालित होगी।

फुटपाथ जैसी जिन्दगी जीने वाले बच्चों का होगा पुनर्वास, 30 जून तक खोजने का चलेगा अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल सक्षम नीति-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत प्रदेशभर में सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों के स्थायी रेस्क्यू, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

1 जून से 30 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में संयुक्त बचाव दल, जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की टीमों द्वारा बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, अपशिष्ट संग्रहण तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के तोसीर, लेंधरा और बरमकेला क्षेत्र में विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बस स्टैंड, मंदिर, बाजार, स्लम बस्तियों तथा अन्य चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों का

सर्वेक्षण कर बच्चों की पहचान की गई तथा उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई।

मरवाही विकासखंड के होटलों, कबाड़ दुकानों, पेट्रोल पंपों, निर्माण स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी भी प्रदान की गई।

नगर पंचायत छुईखदान सहित बस स्टैंड, गैरेज, होटल, ढाबों, ईंट भट्ठों और श्रमिक बस्तियों में सघन अभियान चलाकर बाल श्रम, भिक्षावृत्ति तथा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान एवं पुनर्वास कार्यवाही की गई।

बालोद जिले में बस स्टैंड, होटल, पान ठेला, कबाड़ी दुकानों, मंदिर परिसरों एवं बाजार क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। टीमों ने बाल श्रमिकों, भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान कर आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय सुनिश्चित किए।

हमने बनाया है हम ही संवारेंगे

ढाई साल में बनाए 10.60 लाख ग्रामीण आवास प्रतिदिन सर्वाधिक आवास बना रहा छत्तीसगढ़

- सरकार ने निर्माण के लिए उपलब्ध कराए 26,908 करोड़
- सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नींव - मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। 'हमने बनाया है हम ही संवारेंगे' के सूत्र वाक्य के साथ छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास में लगी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार अपनी पहली कैबिनेट के संकल्प को तेजी से पूरा करने में लगी है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पिछले ढाई वर्षों में 10 लाख 60 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।

बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे अधिक 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए हैं। प्रतिदिन पूर्ण किए जा रहे आवासों की संख्या में भी छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्य में अभी रोज 1600 से अधिक मकानों के निर्माण पूरे किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की कमान संभालने के अगले ही दिन मंत्रालय में अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए 18 लाख आवासों के निर्माण का संकल्प लिया था। राज्य शासन अपने इस संकल्प को तेजी से पूरा करने में लगी है। सरकार ने उस वक्त जिन 18 लाख 12 हजार 742 आवासों के निर्माण का संकल्प लिया था, उनमें 2 लाख 46 हजार 215 अपूर्ण आवास, वर्ष 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6 लाख 33 हजार 438 आवास, आवास प्लस की सूची के सभी 8 लाख 19 हजार 999 आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के सभी 47 हजार 090 आवास शामिल थे।

सरकार इनके साथ ही वनांचलों में पीएम जनमन योजना के 33 हजार 601 और नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विशेष परियोजना के तहत 15 हजार अतिरिक्त आवास भी बना रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास ने आवास प्लस 2.0-2024 के अंतर्गत ऐसे गरीब जिनके आवास कच्चे हैं, उनका सर्वे किया है। उनके लिए भी आवास निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने पहले दिन से ही 18 लाख आवासों के निर्माण के संकल्प को पूरा करने पूरी गंभीरता, सक्रियता और प्रतिबद्धता से काम करना शुरू कर दिया था। इन आवासों को तेजी से पूरा कर गरीबों के पक्के मकान के सपनों को साकार करने सरकार ने 26 हजार 908 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछली सरकार से विरासत में मिले अपूर्ण मकानों के साथ ही जरूरतमंदों के लिए तेजी से नए आवास स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर उन्हें पूरा किया है। सरकार अपने इस संकल्प को पूरा करने किस रफ्तार से काम कर रही है, इसका प्रमाण है कि पिछले वर्ष (2025 में) अप्रैल से अक्टूबर तक राज्य में प्रतिदिन करीब 2000 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। अभी भी रोज 1600 मकानों को पूरा किया जा रहा है। देश में छत्तीसगढ़ में रोजाना सबसे अधिक संख्या में प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी इस महती संकल्प को पूरा करने और इसे पर्याप्त गति देने महिला स्वसहायता समूहों को भी जोड़ा है। स्वसहायता समूहों की दीदियां डीलर दीदी और रानी मिस्त्री बनकर इस महाभियान में हाथ बटा रही हैं। हजारों महिलाएं इससे लखपति दीदी बनी हैं। गांव-गांव में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों ने छोटे-छोटे लेन-देन को गांव में ही सुलभ बनाया, जिससे आवास निर्माण के संकल्प को धरातल पर उतारने में बड़ी मदद मिल रही है।

इंवेस्टमेंट के लिए रेड-कार्पेट 9580 करोड़ के प्रस्ताव मिले

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछा हुआ है।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है। छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन भी मौजूद थे।

बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोग का बड़ा एक्शन : 9 नाबालिग मुक्त, 20 को संरक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बच्चों के संरक्षण हेतु प्रदेशभर में विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चों, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चों तथा रायपुर जीआरपी के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों को संरक्षण में लिया गया।

इसी क्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के उरला स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में विशेष औचक छापामार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से गंभीर एवं जोखिमपूर्ण प्रकृति का कार्य कराया जा रहा था। मौके से 9 बच्चों को

तत्काल संरक्षण में लेकर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था, जो बिहार का रहने वाला है। मामले में संबंधित ठेकेदार, बच्चों को यहां लाने वाले अन्य व्यक्तियों तथा संभावित बाल तस्करी के पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण एवं अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने के तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 एवं 143 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाल श्रम एवं संभावित बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, विशेषकर तब जब उनसे जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कराया जाता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आयोग पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर कार्रवाई

रायपुर। मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन और वंश वृद्धि को संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है। इस अवधि में अधिकांश जल संसाधनों में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा 3(2) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार नदी, नाले, जलाशय एवं अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों में मछली पकड़ना निषिद्ध रहेगा। ऐसे छोटे तालाब, जिनका संबंध नदी या नालों से नहीं है, तथा केज कल्चर गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंद ऋतु के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मत्स्य विभाग ने मछुआरों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में मत्स्याखेट से

बकरी की सिजेरियन डिलीवरी तीन स्वस्थ मेमनों ने लिया जन्म

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर के टाटीबन्द क्षेत्र की निवासी भागा ध्रुव की बकरी 24 घंटे से प्रसव पीड़ा में थी। सामान्य प्रसव संभव न होने पर वह ऑटो से बकरी को जिला पशु चिकित्सालय, बैरनबाजार लेकर पहुंचीं। जांच में पता चला कि गर्भाशय मार्ग में रुकावट के कारण सामान्य डिलीवरी संभव नहीं है।

संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाओं के मार्गदर्शन में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन का निर्णय लिया। जिला पशु चिकित्सालय के डॉ. किरण चौधरी, डॉ. पदम् जैन, डॉ. देवप्रभा और वेटनरी कॉलेज अंजोरा, दुर्ग के पांच इंटर्न की टीम ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

तीनों मेमने पूरी तरह स्वस्थ हैं। श्रीमती भागा, जो बकरी पालन के साथ घरों में काम कर जीवन यापन करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके अपने संतान नहीं है, इसलिए वह बकरियों को बच्चों की तरह पालती हैं। अब उनके पास कुल 10 बकरियां हो गई हैं।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव-गांव पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

रायपुर। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ संभावित जलजनित एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिला में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखंडों में मितानिनों के सहयोग से जल स्त्रोतों के शुद्धिकरण का कार्य तेज किया गया है। अब तक लगभग तीन हजार कुओं का शुद्धिकरण किया जा चुका है, जबकि शेष जल स्त्रोतों में भी यह कार्य लगातार जारी है। संवेदनशील और दुर्गम ग्रामों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीएमएचओ डॉ. विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों की संयुक्त टीमें गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है।

ज्ञान भारतम्-राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण

कबीरधाम में मिली 375 साल पुरानी 38 पांडुलिपियां

- भोरमदेव और मड़वा महल के ऐतिहासिक अभिलेख मिले
- बंगला में लिखी पाक कला की पुस्तिका भी मिली
- गीता, गजेन्द्र मोक्ष और गीत गोविन्द की प्रतियां भी

श्रीकंचनपथ समाचार

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम (कवर्धा) जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित 'ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान' के तहत जिले में इतिहास, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े 38 दुर्लभ व महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों की पहचान की गई है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान ने जिले की बौद्धिक विरासत के ऐसे अनमोल साक्ष्य उजागर किए हैं, जो मध्यभारत के इतिहास को एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे।

सर्वेक्षण में मिला सबसे अनोखा और

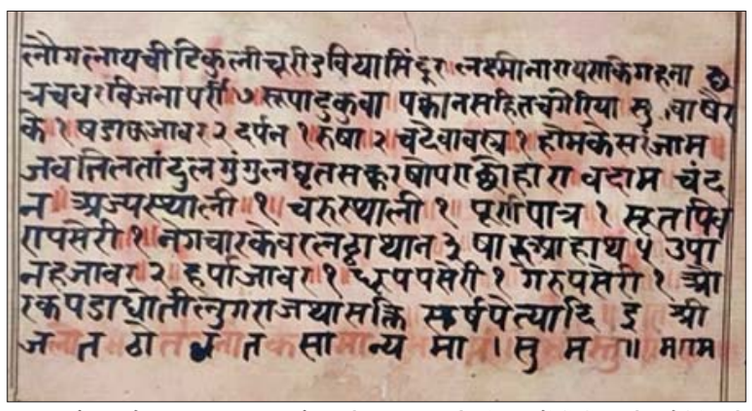

महत्वपूर्ण दस्तावेज लगभग 375 वर्ष पुरानी तालपत्र (पाम लीफ) पांडुलिपि है। बंगाली भाषा में लिखी गई यह पांडुलिपि प्राचीन पाक-कला (कुकिंग आर्ट) से संबंधित है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दुर्लभ दस्तावेज उस दौर की जीवनशैली, खानपान संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को समझने का एक बेहद अहम और जीवंत स्त्रोत है।

इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान भारतीय भक्ति साहित्य और काव्य परंपरा से जुड़ी कई अमूल्य कड़ियों की पहचान की गई है। सन 1867 में किया गया प्रसिद्ध भोरमदेव शिलालेख का अनुवाद, सन 1898 का मड़वा महल शिलालेख का पद्यात्मक (काव्य रूप) अनुवाद शामिल हैं।

ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और वैदिक परंपराओं की झलक

खगोल विज्ञान, ज्योतिष और वैदिक चिंतन को दर्शाती कई पोथियां भी इस अभियान में सामने आई हैं। इनमें ब्रह्मांड के चित्रांकन से संबंधित संस्कृत दस्तावेज और जैमिनी परंपरा की पोथियां शामिल हैं। प्राप्त दस्तावेजों में से अधिकांश कवर्धा निवासी आदित्य श्रीवास्तव तथा अजय कुमार चंद्रवंशी के निजी संग्रह से मिले हैं। इसके अलावा, ग्राम बसनी के सुभाष पाण्डेय के निजी संग्रह से महामृत्युंजय स्त्रोत, संध्या विधि, तांत्रिक संध्या, श्राद्ध पद्धति, और जलाशयराम मठोत्सर्ग विधि जैसी कई दुर्लभ तांत्रिक व वैदिक अनुष्ठान पद्धतियों की पांडुलिपियां मिली हैं। इन अमूल्य धरोहरों को अब सुरक्षित किया जाएगा। ज्ञान भारतम् अभियान के तहत इन सभी 38 दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा।

कुष्ठ संक्रमण को शून्य करने कार्यशाला आयोजित

- पांच राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव
- विकलांगता रोकथाम और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने पर विशेष जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग के संक्रमण को पूर्णत: समाप्त करने तथा जीरो ट्रांसमिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नया रायपुर में 02 दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा एवं रणनीतिक कार्ययोजना हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) आराधना पटनायक, सचिव स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ संजीव कुमार झा, संयुक्त सचिव भारत

सरकार निखिल गजराज, कुष्ठ रोग प्रकोष्ठ के उप महानिदेशक डॉ. सुनील वी. गिट्टे सहित महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और मध्यप्रदेश के मिशन संचालक, राज्य कुष्ठ अधिकारी व क्षेत्रीय निदेशक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य अमित कटारिया ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति, चुनौतियों और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने कुष्ठ रोग के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, समय पर पहचान सुनिश्चित करने तथा रोग से होने वाली विकलांगता को समाप्त करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

अपने संबोधन में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस क्षेत्रीय कार्यशाला में पांच राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कार्यक्रम प्रबंधक और तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि कु ष्ठ रोग केवल स्वास्थ्य संबंधी चुनौती नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) भी रोगियों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए उपचार के साथ-साथ समाज के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950